राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 210 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,21 जनवरी 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में चार जवान घायल

जम्मू। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के अग्रिम इलाके को निशाना बनाकर की गयी गोलीबारी में सेना के चार जवान घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात एलओसी पार से केरी बट्टल इलाके में गोलीबारी कर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया गया। सूत्रों ने बताया कि इस घटना में चार जवान घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए उधमपुर में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत का निधन

जयपुर। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत का बुधवार को निधन हो गया। वह कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधायक के निधन पर शोक जताया है। गहलोत ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, '' कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से वे बीमार थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले 15 दिन से मैं परिवारजन और डॉक्टरों के संपर्क में था।'' गहलोत ने शोक संतप्त परिजनों को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट ने शक्तावत को हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहने वाले विनम्र प्रतिनिधि के रूप में याद कर शोक जताया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेक नेताओं ने विधायक शक्तावत के निधन पर शोक जताया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार शक्तावत कई दिन से बीमार थे। उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक चार विधायकों का असमायिक निधन हो चुका है जिनमें कांग्रेस के तीन व भाजपा के एक विधायक शामिल हैं। शक्तावत पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले पायलट खेमे में शामिल थे।

मप्र में फिजियोथेरैपी परिषद का होगा गठन : शिवराज

भोपाल। मध्य प्रदेश में फिजियोथेरैपी के लिए अलग से परिषद की स्थापना पर सरकार विचार करेगी, यह आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोग्य भारती के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए दिया। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक आरोग्य भारती के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, ÷प्रदेश में फिजियोथेरैपी के लिए पृथक परिषद की स्थापना पर विचार करेंगे। कोरोना काल में एलोपैथी के साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता का अनुभव किया गया। इस नाते इन चिकित्सा पद्धतियों का रोगों से बचाव में बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, स्वास्थ्य जागरण क्षेत्र में आरोग्य भारती महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। संस्था द्वारा फिजियोथेरैपी काउंसिल के गठन का दिया गया सुझाव महत्वपूर्ण है। फिजियोथेरैपी का विकास जनहित में आवश्यक है। मध्यप्रदेश में इस पद्धति को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान से भेंट करने वालों में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मधुसूदन देशपांडे, डॉ. अशोक वार्ष्णेय, अभिजीत देशमुख और सुमित राणा शामिल थे।

प्रधानमंत्री को गरीबों की वास्तविकता के बारे में जानना चाहिए : चिदंबरम

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समय है कि प्रधानमंत्री को वास्तविकता जानना चाहिए और नौकरशाहों द्वारा बताए गए शौचालयों, आवास और शौच मुक्त जगहों के आंकड़े नहीं दोहराए। पूर्व वित्त मंत्री ने गुजरात के सूरत में एक ट्रक द्वारा 15 प्रवासी मजदूरों को कुचले जाने के संदर्भ में यह टिप्पणी की। चिदंबरम ने एक बयान में कहा, गुजरात में 15 प्रवासी निर्माण श्रमिकों का मारा जाना भारत में गरीबों की वास्तविकता की दिशा में आंखे खोलने वाला है। सरकार पर आरोप लगाते हुए, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने पूछा कि, मजदूर सड़क के किनारे क्यों सो रहे थे? क्या ठेकेदार उन्हें निर्माण स्थल के पास आश्रय देने के लिए बाध्य नहीं है?

ट्रैक्टर रैली में कोर्ट का दखल नहीं : कहा- पुलिस को आदेश जारी करने का अधिकार

शांति का प्रदर्शन करें

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एएस बोबड़े की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है, पुलिस ही इसपर अनुमति देगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस से इस पर फैसला लेने को कहा था। वहीं आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि हम मामला लंबित नहीं रखेंगे। पुलिस तय करे, उसे अधिकार है। बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच वे गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग हैं। इसी मसले पर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक भी तय है।

बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच वे गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग हैं। इसी मसले पर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक भी तय है। सरकार का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर यदि ऐसे हजारों लोग दिल्ली में आएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कतें होगी। जबकि किसानों का कहना है कि वो परेड समाप्त होने के बाद अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होगी।

टिकरी बॉर्डर पर दो और किसानों की मौत

मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शन में मंगलवार रात टिकरी बॉर्डर पर दो और किसानों की मौत हो गई। मृतकों में एक किसान हरियाणा और दूसरा पंजाब का है। इसके अलावा कुंडली बॉर्डर पर भी लुधियाना के जगजीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। वहीं मंगलवार को टिकरी बॉर्डर पर जहर खाने वाले किसान जयभगवान राणा को भी नहीं बचाया जा सका और अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। अमर उजाला की खबर के अनुसार, टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आए पंजाब के 65 वर्षीय किसान धन्ना सिंह की मंगलवार देर रात हृदयाघात से मौत हो गई। वह बहादुरगढ़ बाईपास पर नयागांव चौक के निकट ठहरे थे। उनके शव को नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ के शवगृह में रखा गया है। परिजनों को सूचना भेज दी गई है और अब उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। वह पंजाब के पटियाला के गांव तंगू के रहने वाले थे।

शांतिपूर्ण मार्च की तैयारियां जोरों पर

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अपनी निर्धारित ट्रैक्टर रैली को लेकर अनिश्चितता की स्थिति के बीच, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार को कहा कि शांतिपूर्ण मार्च की तैयारी पूरे जोरों पर है और वापस हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक इस रैली को हालांकि आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने घोषणा की है कि हजारों किसान 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।

सरकार ने दिया कृषि कानूनों पर अस्थाई रोक का प्रस्ताव, किसान नेताओं ने ठुकराया

नई दिल्ली। किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने किसानों के सामने दो प्रपोजल दिए हैं। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा स्स्कपर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि, किसान कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। सरकार के प्रपोजल पर किसानों ने अलग बैठक की। उन्होंने अपना फैसला अभी नहीं बताया है। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।

विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की थी तो किसानों ने केवल कानून वापसी की ही मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। MSP को लेकर हमने चर्चा की बात कही तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि NIA का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग किसान धन्ना सिंह की बुधवार को मौत हो गई, मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाई है।

अमेरिका में बाइडेन युग

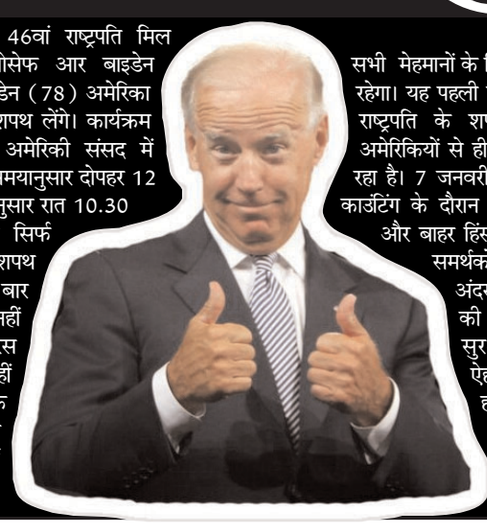

अमेरिका को आज 46वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। डेमोक्रेट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन (78) अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में बुधवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे) होगा। बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में पद की शपथ लेंगे। समारोह इस बार हमेशा की तरह भव्य नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से भीड़ नहीं जुटेगी। इस बार एक हजार से 1200 लोग ही शपथ ग्रहण में हिस्सा ले पाएंगे।

सभी मेहमानों के लिए सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल रहेगा। यह पहली बार होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अमेरिकियों से ही खतरा महसूस किया जा रहा है। 7 जनवरी को इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग के दौरान कैपिटल हिल्स के अंदर और बाहर हिंसा हुई थी। उस वक्त ट्रम्प समर्थकों ने अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा ऐहतियात बरत रही हैं। यहां हम आपको इस शपथ ग्रहण समारोह यानी इनॉगरेशन डे से जुड़े लाइव अपडेट्स दे रहे हैं।

व्हाइट हाउस का नमस्ते ट्रंप

अमेरिकी इतिहास के वह राष्ट्रपति जो सबसे विवादित हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने एक दिन में औसतन 12 झूठे दावे किए। अपने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ट्विटर और फेसबुक पर बैन कर दिए गए। वह राष्ट्रपति जो चुनाव हार जाने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं हुए। आब वे पूर्व हो जाएंगे। अब सवाल है कि ट्रम्प व्हाइट हाउस से कहां जाएंगे? उन पर जो महाभियोग चल रहा है क्या वह अब खत्म हो जाएगा? राजनीति में आगे क्या करेंगे? अपनी पार्टी में उनका क्या कद रहेगा? उनके बिजनेस का क्या होगा? क्या पद से हटने के बाद जेल भी जा सकते हैं? ट्रम्प तो खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बाकी राष्ट्रपतियों से थोड़े अलग हैं। वे प्रेसिडेंट ऑफिस के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले राष्ट्रपति हैं। 1869 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के बाद ट्रम्प पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। ट्रम्प ने घोषणा की है कि व्हाइट हाउस से निकलने के बाद वे फ्लोरिडा के अपने मेर-ए-लागो प्राइवेट क्लब में रहेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया यूपी के ग्रामीणों को तोहफा, बोले- आवास योजना से जुड़े करोड़ों के सपने

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6.1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में बुधवार को 2,690 करोड़ रुपये की धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर किया। पीएम मोदी की ओर से वर्ष 2020-21 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.3 लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण की पहली किस्त तथा 80 हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त की धनराशि ट्रांसफर की गई है।

इस दौरान पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी के नन्?हें सिंह, चित्रकूट से राजकुमारी, वाराणसी की कमला देवी और अयोध्?या की कुमकुम, सहारनपुर की बाला से बात भी की और शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि यह जो घर मिला है वह बहुत बड़े संबल का काम करेगा। घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इससे नया आत्मविश्वास आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को बहुत जल्द सपनों का घर मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया है। यह समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभ समय में घर बनने के लिए धनराशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही देश में कोरोना वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब आप सभी के जीवन का एक सपना पूरा हो रहा है। यह खुशी आपके जीवन में सुविधा भरे यही मेरी कामना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई भी देता हूं। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। इतना अदम्य साहस सेवा और सत्य की शक्ति से ही आता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पांच वर्ष पहले आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद और सपने जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को यह विश्वास दिलाया है कि आज नहीं तो कल मेरा भी घर हो सकता है।

वेतन एक मौलिक अधिकार है: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज नगर निगमों की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकता और वेतन पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ, दिल्ली नगर निगमों, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा, समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने का कारण धन की कमी बताया गया है। ये एक बहाना नहीं हो सकता क्योंकि वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वेतन का भुगतान नहीं करने का सीधा असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

" कोर्ट ने कहा, समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने का कारण धन की कमी बताया गया है ये एक बहाना नहीं हो सकता क्योंकि वेतन और पेंशन लोगों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वेतन का भुगतान नहीं करने का सीधा असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

अदालत ने आगे कहा कि यह बहुत जरूरी है कि निगमों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाय, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और जो महामारी के समय में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। बेंच ने आगे कहा कि पैसे की कमी बहाना नहीं हो सकती और न ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। वेतन और पेंशन के भुगतान को अन्य खचरें से ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। अगली सुनवाई 21 जनवरी तक स्थगित करते हुए कोर्ट ने कहा, इसलिए, हम नगर निगमों को निर्देश देते हैं कि वो विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का ब्योरा दे।

स्कूली छात्रों के लिए आसान होगी नेजल वैक्सीन

नई दिल्ली । केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के क्लीनिकल ट्रायल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। हालांकि इस मसले पर अभी अंतिम फैसला भारतीय दवा महानियंत्रक को लेना है लेकिन इस वैक्सीन को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।

विशेषज्ञ इस वैक्सीन को बच्चों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रहे हैं। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन आसानी से स्कूली बच्चों को दी जा सकेगी। भले ही स्कूली बच्चों में कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा कम होता हो लेकिन ये दूसरे लोगों को संक्रमण फैला सकते हैं यानी ये कोरोना के वाहक साबित हो सकते हैं। ऐसे में यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बेहद मददगार साबित होगी।

प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ अब तक जो भी वैक्सीन आई हैं वे बच्चों के लिए अनुमोदित नहीं हैं। बच्चों पर इन वैक्सीन का अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि बच्चों पर वैक्सीन का परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं। डॉ. गुलेरिया ने कहा कि एक बार जब बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और संक्रमण को यदि घर लाते हैं तो वे इसे अपने माता-पिता या दादा-दादी में फैला सकते हैं।

बच्चों के लिए बहुत आसान होगा नेजल टीका

एक सवाल के जवाब में डॉ. गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के खिलाफ बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द आ सकती है। भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन के अनुमोदन के लिए कोशिशें कर रहा है। इस तरह का नेजल टीका बच्चों को दिया जाना बहुत आसान होगा क्योंकि यह एक स्प्रे है। यदि इस वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो इससे टीकाकरण भी बेहद आसान होगा। महज आधे घंटे में ऐसा टीका पूरी कक्षा के बच्चों को दिया जा सकता है।

डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि टीकाकरण संक्रमण से जंग जीत चुके लोगों के लिए भी जरूरी है। ऐसे लोगों को स्वस्थ्य होने के चार से छह हफ्ते बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि किसी वजह से शरीर के अंदर एंटी बॉडीज की संख्या कम हो गई है तो वैक्सीन लगने के बाद इसमें इजाफा हो जाएगा। दरअसल, एक कार्यक्रम में गुलेरिया से एनडीआरएफ कर्मचारियों ने पूछा कि क्या वैक्सीन लेना उस व्यक्ति के लिए भी जरूरी है जो संक्रमण से ठीक हो चुका है। मालूम हो कि देश में दो वैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

वहीं भारत बायोटेक के मुताबिक नेजल वैक्सीन इंसानी शरीर के भीतर संक्रमण को तो रोकेगी ही साथ ही संक्रमण के प्रसार पर भी लगाम लगाएगी। भारत बायोटेक का कहना है कि चूहे पर ट्रायल के दौरान यह प्रभावशाली पाई गई है।

सिख समाज का धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदान देश हमेशा याद रखेगा: योगी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख समाज का धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। धर्म की रक्षा के लिए चार साहिबजादो ने खुद को बलिदान कर दिया। दरअसल, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बुधवार को राजधानी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे यहियागंज पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री ने कहीं। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, विधि एवम न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुख्?यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और पूजा की।

फूलों से सजा दरबार हाल, गुरु ग्रंथ साहिब पर प्रकाश के साथ मत्था टेकती संगत, गुरु की जीवनी पर प्रकाश डालते हेड ग्रंथी और लंगर सेवा करने के लिए संगतों की कतार। कुछ ऐसे ही माहौल में बुधवार को सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव मनाया। वहीं, ऐतिहासिक गुरुद्वारे यहियागंज में प्रकाशोत्सव का विशेष महत्व है। यहां गुरु गोविंद सिंह साहिब ठहरे थे।

गुरुद्वारा यहियागंज में ठहरे थे गुरु गोविंद सिंह÷ बिहार के पटना साहिब में जन्मे गुरु गोविंद सिंह 1670 में छह वर्ष की आयु में अपनी माता माता गुजरी और माता कृपाल जी महाराज के साथ आनंदपुर साहिब से पटना साहिब जाते समय दो महीने 13 दिन गुरुद्वारा यहियागंज में ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा हस्त लिखित गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरुद्वारे में मौजूद है। हुक्म नामे भी गुरुद्वारे की शोभा बढ़ा रहे हैं।

गुरुद्वारा नाका हिंडोला में हुआ विशेष प्रकाश÷ लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा नाका हिंडोला में विशेष दरबार सजाया गया। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन के पहले दिन पंच प्यारे की अगुआई में नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। बुधवार को कोरोना संक्रमण की गाइड लाइन के साथ आयोजन किया गया। लंगर सेवा के लिए सेवादारों की कतार लगी रही। महिलाएं व पुरुष सेवादार लगे रहे। लंगर के साथ समापन हुआ। गुरुद्वारा यहियागंज के सचिव मनमोहन सिंह हैप्पी ने बताया कि सुबह फूलों की वर्षा के साथ प्रकाशोत्सव मनाया गया। सजे दरबार हाल में सुबह से ही संगतों की कतार लगी रही।

अर्जेंटीना में भूकंप के जोरदार झटके

अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। यहां के सान जुआन प्रांत में देर रात 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। तेज झटकों से सहम गए लोग आधी रात को अपने घरों से बाहर भागने लगे। भूकंप के बारे में जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) ने जानकारी दी। ऐसे में अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने कहा है कि भूकंप के चलते सुनामी से जुड़ी कोई

चेतावनी फिलहाल तो जारी नहीं की गई है।

भूकंप के जोरदार झटके महसूस

अर्जेंटीना में भूकंप के ताबड़तोड़ झटकों से लोगों में खौफ अभी भी बना हुआ है। बीती रात लोगों ने सड़कों पर गुजरी। भूकंप के झटके इतने तेज थे, जिनसे धरती में जोरदार कपकपाहट थी। हालाकिं खबर लिखे जाने तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। बता दें, उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना चिली से लगा हुआ है, इसलिए यहां भी भूकंप से झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र पोर्सिटो से 27.6 किमी दूर दक्षिण पश्चिम में था। ये भूकंप 14 किलोमीटर की गहराई पर आया था।

भूकंप में कम से कम 81 लोगों की मौत

बीते दिनों इससे पहले इंडोनेशिया में बहुत ही भीषण भूकंप आया था। जिसमें करीब 100 से ज्यादा इमारते गिर गई थी। पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई थी। झटके इतने भयावह थे कि कई घरों और इमारतों को तबाह कर दिया। फिलहाल बचाव अभियान को तेजी से चलाया गया था। फिर भी इस भूकंप में कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं राष्ट्रीय आपदा मोचन एजेंसी के प्रवक्ता रादित्य जति का ऐसा कहना है कि भूंकप से सबसे अधिक ममूजू शहर और सुलावेसी द्वीप पर माजेने प्रभावित हुए हैं। जबकि घायल हुए करीब 800 लोगों में से आधे लोगों का इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रूस-भारत करीब: दोस्ती का बड़ा दावा

मास्को। भारत और रूस के रिश्तों में आई दूरी की अटकलों को रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लवरोफ़ ने ख़ारिज करते हुए बड़ा ब्यान जारी किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लवरोफ़ ने साफ़ कहा कि भारत रूस का अहम साथी है और भविष्य में भी रहेगा। बता दें कि रूस- भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौतों को लेकर चिंतित है। रूस का कहना है कि भारत- रूस से स-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, ऐसे में अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है।

दरअसल, हाल ही में नई भारत ने रूस से शक्तिशाली S-400 मिसाइल सिस्टम प्रणाली की खरीद की डील की है। एस-400 मिसाइल सिस्टम से भारत को रक्षा कवच मिल जाएगा।हालंकि भारत और रूस की इस डील को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो इस सौदे को रद्द कर दे। अमेरिका ने भारत को पांबदी की भी चेतावनी दी थी। अमेरिका का कहना है कि इस डील के लिए अमेरिका द्वारा भारत को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

भारत-रूस की दोस्ती की दी वजह

अब इस पूरे प्रकरण में रुसी विदेश मंत्री सर्गेइ लवरोफ़ ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि भारत और रूस के बीच की साझेदारी बहुत विस्तृत है। दोनों देशों के बीच का रिश्ता बहुत ख़ास हैं। चाहे अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, इनोवेशन के स्तर पर, हाइटेक या फिर सैन्य तकनीक के स्तर पर, भारत और रूस काफी करीब हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सर्गेइ लवरोफ़ ने कहा कि उनके सत्ता में आने के बाद हमारी रणनीतिक साझेदारी एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुई है। संयुक्त राष्ट्र या ब्रिक्स स्तर पर दोनो देशो के बीच नज़दीकी राजनीतिक समन्वय है। उन्होने बताया कि भारत और पाकिस्तान शंघाई को-ऑपरेशन कॉर्पोरेशन में भी हैं। इन मंचों से पूरे महाद्वीप में मिलकर काम करते हैं। इसे व्यापक तौर पर एशिया-पैसिफिक कहा जाता है। सर्गेई ने भारत से रिश्ते को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर चिंता जाहिर की। उन्होने कहा, अमेरिका प्रायोजित अवधारणा में इंडो पैसिफिक की व्याख्या कुछ और है। क्वॉड गुट में यूएएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया हैं। इसे माइक पॉम्पियो ने इंडो पैसिफिक इलाक़े में स्वतंत्र आवाजाही के लिए सबसे अहम बताया है।

यूएस में नई सरकार

मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं; एक्सपर्ट बोले- भारत-अमेरिका के लिए चीन ही

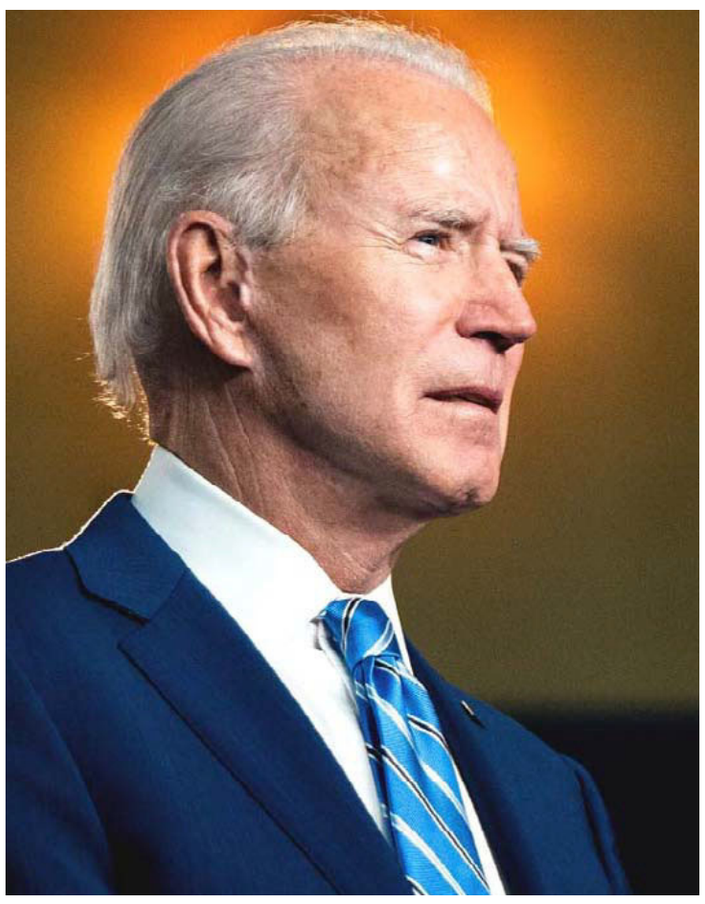

वॉशगिंटन। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। अमेरिका में चुनाव और नई सरकार के गठन के बीच करीब 11 हफ्ते का अंतराल यानी गैप होता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट की ट्रांजिशन टीम इस दौरान अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार करती है। मंत्रियों को यहां सेक्रेटरी कहा जाता है। 15 मुख्य विभाग है। इनके नाम भावी राष्ट्रपति तय करता है। इस बारे में विस्तार से चर्चा आगे करेंगे।

बाइडेन को लेकर भारत में एक सवाल हर कोई जानना चाहता है। और वो ये कि भारत को लेकर उनकी नीति क्या और कैसी होगी? वे ट्रम्प के रास्ते पर ही चलेंगे या कुछ बदलाव करेंगे। इस मुद्दे को हमारे एक्सपर्ट्स से समझेंगे। तो आइए अमेरिका के नई सरकार से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर जानकारी हासिल करते हैं।

मंत्रियों के नाम कैसे तय होते हैं?: अमेरिका में कैबिनेट का गठन भारत से थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के अलावा 15 मंत्री होते हैं। ये सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं। बाद में ये दूसरे अधिकारियों में काम का बंटवारा करते हैं यानी अपनी टीम बनाते हैं। एक रोचक तथ्य- अमेरिका में मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो शख्स सांसद हो या सियासत से जुड़ा हो। हो सकता है कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। कई बार तो विरोधी दल के नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है।

आसान भाषा में कहें, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी नजर में योग्य हो। 15 सेक्रेटरीज के अलावा कुछ और लोगों को कैबिनेट रैंक मिलती है। इनमें व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ और यूएन में स्थाई राजदूत शामिल हैं। ऐसे 7 या 8 लोग हो सकते हैं।

whitehouse.gov के मुताबिक, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैबिनेट मेंबर्स के नाम तय करते हैं। शपथ लेने के बाद सीनेट इन नामों पर मुहर लगाती है। कुछ नामों को लेकर आपत्ति भी आ सकती है। सीनेट की कमेटियां संबंधित मंत्री के बारे में जानकारी जुटा सकती हैं। इसकी वजह यह है कि जो व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, उसका रिकॉर्ड बेदाग रहे।

भारत की नजर तीन मंत्रियों पर ज्यादा: विदेश मंत्री: 58 साल के एंटनी ब्लिंकेन को बाइडेन ने विदेश मंत्री बनाया है। सुपरपावर अमेरिका में विदेश मंत्री बाहरी दुनिया के लिए सबसे अहम होता है। भारत के लिए भी ऐसा ही है। ब्लिंकन और बाइडेन का रिश्ता काफी पुराना और दोस्ताना है। ओबामा के दौर में जब बाइडेन उप राष्ट्रपति थे, तब ब्लिंकेन विदेश राज्य मंत्री और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। भारत के प्रति उनका रवैया नर्म रहा है।

रक्षा मंत्री : 67 साल के लॉयड जे ऑस्टिन नए रक्षा मंत्री होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, फोर-स्टार पूर्व जनरल ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे। वे बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं और इराक-अफगानिस्तान में मैदानी जंग के अनुभवी है। भारत और अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में भी हिस्सा ले चुके हैं। बहुत कम बोलने वाले ऑस्टिन को सख्त मिलिट्री अफसर माना जाता है।

जेक सुलिवान: 44 साल के सुलिवान अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे।

वे बाइडेन के बेहद करीबी और पसंदीदा व्यक्ति माने जाते हैं। ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के साथ काम कर चुके हैं।

तेज तर्रार और मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सुरक्षा मामलों पर बाइडेन उनसे ही सलाह लेते रहे हैं। 2012 में ईरान-अमेरिका न्यूक्लियर डील में उनका अहम रोल था। बाद में इस डील को ट्रम्प ने रद्द कर दिया था।

कोरोना दुनिया में :13 देश कोरोना मुक्त

लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका समेत 131 देशों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन

वॉशगिंटन। दुनिया के कई देशों में कोरोना के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इस बीच, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वीकली रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के 13 देश और आइलैंड्स अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। यहां अब कोरोना का कोई केस नहीं है। हालांकि, यहां अभी भी ऐहतियात बरतने की जरूरत है। चिंता की बात ये है कि दुनिया के 131 देशों में संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। इसमें अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील, यूके, फ्रांस जैसे बड़े देश शामिल हैं। भारत अभी क्लस्टर्स ऑफ केस की कटेगिरी में है। मतलब अभी यहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं शुरू हुआ है।

जनवरी में सबसे ज्यादा मरीज मिले, सबसे ज्यादा मौतें भी

दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन ड्राइव भले शुरू हो चुका है लेकिन, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कम से कम आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जनवरी के इन 18 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। 8 जनवरी को दुनिया में सबसे ज्यादा 8 लाख से ज्यादा मरीज मिले। इसके पहले एक दिन में कभी भी इतने मरीज नहीं मिले थे। इसी तरह 13 जनवरी को सबसे ज्यादा 16 हजार 537 लोगों ने जान गंवाई।

अब तक 9.60 करोड़ केस

दुनिया में अब तक 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात ये है कि इनमें 6 करोड़ 86 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 20 लाख 49 हजार से ज्यादा हो चुकी है। 2.53 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें 1.12 लाख मरीजों की हालत गंभीर है। ये आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं।

यूके में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 3 महीने तक फिर से स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अप्रैल से हालात सामान्य होने के बाद स्कूल खोले जा सकेंगे।

यूएस में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। सोमवार को यहां 1.42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। 1422 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 2 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 45 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 96 लाख मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। ??

कोरोना प्रभावित टॉप-10 देशों में हालात

देश	सक्रमित	मौतें	ठीक हुए
अमेरिका	24,626,376	408,620	14,551,685
भारत	1,05,82,647	1,52,593	1,02,27,852
ब्राजील	8,512,238	210,328	7,452,047
रूस	3,591,066	66,037	2,978,764
यूके	3,433,494	89,860	1,546,575
फ्रांस	2,894,347	70,142	208,071
तुर्की	2,387,101	23,997	2,262,864
इटली	2,368,733	81,800	1,729,216
स्पेन	2,252,164	53,314	एन/ए
जर्मनी	2,041,935	47,227	1,672,000

जम गया रेगिस्तान: सहारा रेगिस्तान पर बर्फ की चादर, तापमान -3 डिग्री पहुंचा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा

रियाद। आमतौर पर यहां का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन बदले मौसम के साथ अब यहां का तापमान माइनस 3 डिग्री पहुंच चुका है। इसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया में जनवरी में बर्फ पड़ने लगती है, वहीं अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में ऐसा नहीं होता। इस बार वहां भी बर्फबारी के कारण रेत पर सफेद चादर बिछ गई है। सऊदी अरब के असीर प्रांत में बर्फबारी हुई है। इससे स्थानीय लोग खुश हैं। उनमें उत्सुकता का माहौल है। रेगिस्तान पर बर्फबारी के बाद यहां विदेशी पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं।

वैज्ञानिकों का दावा- 15 हजार साल में हरा-भरा हो सकता है रेगिस्तान

समुद्र तल से करीब एक हजार मीटर ऊपर और एटलस पर्वत से घिरे अइन सेफरा को रेगिस्तान का मुख्य द्वार माना जाता है। उत्तरी अफ्रीका का अधिकतर हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा है। यह हजारों साल से अपने तापमान और नमी की वजह से चर्चा में रहता है। अइन सेफरा अभी सूखा पड़ा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 15 हजार साल में यह रेगिस्तान एक बार फिर हरा-भरा हो सकता है।सहारा का रेगिस्तान। आमतौर पर यहां का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन बदले मौसम के साथ अब यहां का तापमान माइनस 3 डिग्री पहुंच चुका है। इसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया में जनवरी में बर्फ पड़ने लगती है, वहीं अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में ऐसा नहीं होता। इस बार वहां भी बर्फबारी के कारण रेत पर सफेद चादर बिछ गई है। सऊदी अरब के असीर प्रांत में बर्फबारी हुई है। इससे स्थानीय लोग खुश हैं। उनमें उत्सुकता का माहौल है। रेगिस्तान पर बर्फबारी के बाद यहां विदेशी पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं।

दहशत में डी-फैमिली: मसूद अजहर पर सख्ती से डरा दाऊद इब्राहिम, परिवार के खास सदस्यों को पाकिस्तान से बाहर भेजा

करांची। दुनिया भर से आ रहे दबाव की वजह से पाकिस्तान अपने यहां आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर रहा है। हाल में उसने जैश चीफ मसूद अजहर और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी पर सख्ती की है। इसे भांपते हुए भारत के मोस्टवांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम ने भी अपने परिवार के खास सदस्यों को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया है। इनमें दाऊद का बेटा और दो छोटे भाइयों के बच्चे शामिल हैं।

भारत के खुफिया सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इससे पहले दाऊद ने अपनी बड़ी बेटी माहरुख के लिए पुर्तगाली पासपोर्ट का इंतजाम किया था। माहरुख की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मिंयादाद के बेटे जुनैद से हुई है। दाऊद अभी कराची से अपना कारोबार चला रहा है। ????

छोटा भाई कासकर पहले से दुबई में

सूत्रों के मुताबिक, दाऊद का छोटा भाई मुस्तकीम अली कासकर पहले से ही दुबई में बसा हुआ है। वह संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर में डी कंपनी के वैध कारोबार की देखभाल करता है। मुस्तकीम की संयुक्त अरब अमीरात में गारमेंट फैक्ट्री है। कथित तौर पर वह डी फैमिली के उन करीबी रिश्तेदारों की देखरेख करता है, जिन्हें हाल में कराची से दुबई भेजा गया था।

खुफिया सूत्रों ने बताया कि कराची में डिफेंस हाउसिंग एरिया में रहने वाला दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम का भी पिछले दो हफ्तों से पता नहीं है। दाऊद का खास और उसका वसूली का काम संभालने वाला छोटा शकील भी इन दिनों कहीं छिपा हुआ है।

अनीस इब्राहिम ने भी बच्चों को शिफ्ट किया

1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अनीस इब्राहिम ने डी कंपनी का कारोबार देखने के लिए पहले ही अपने बच्चों को मिडिल ईस्ट के देशों में शिफ्ट कर दिया था। अभी वह सिंध प्रांत के कोटली इंडस्ट्रियल एरिया में मेहरान पेपर मिल का काम देखता है। यह मिल कराची से 154 किमी दूर है। पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सरपरस्ती में इस पेपर मिल में कथित रूप से जाली भारतीय करंसी की छपाई होती है। इससे पहले अमेरिकी एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ने पाकिस्तान सरकार से इस पेपर मिल को बंद कराने के लिए कहा था।

दाऊद की देखरेख में रह रहे भाइयों के बच्चे

दाऊद के एक भाई नुरुल हक की पाकिस्तान में मौत हो चुकी है। उसके सबसे बड़े भाई साबिर अहमद की 1981 में मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साबिर का परिवार बाद में पाकिस्तान चला गया और दाऊद की देखरेख में रह रहा है। सूत्रों ने बताया कि डॉन का बेटा मोइन कासकर अक्सर लंदन आता-जाता है। उसने ब्रिटेन के जाने-माने कारोबारी की बेटी से शादी की है। वह पत्नी के साथ 2019 तक कराची में दाऊद के क्लिफ्टन बंगले में रह रहा था। मोइन कराची, लाहौर और यूएई में डी-कंपनी के अरबों रुपए के रियल एस्टेट कारोबार को संभालता है।

मसूद अजहर के खिलाफ वारंट, लखवी अरेस्ट

हाल में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जैश के चीफ पर इस कार्रवाई को देखते हुए सभी का ध्यान दाऊद इब्राहिम पर टिक गया है। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी की गिरफ्तारी के बाद भी डी-कंपनी परेशानी महसूस कर रही थी।

सूत्रों का कहना है कि दाऊद के समधी जावेद मियांदाद के पुराने साथी प्रधानमंत्री इमरान खान शायद ही दाऊद पर कोई कार्रवाई करें। पहले भी जब उसका सिंडिकेट दुनिया की एजेंसियों के रडार पर आया है, डी-कंपनी अपने खास सदस्यों को पाकिस्तान से बाहर भेजती रही है।

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नहीं हैं एकमत

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच पिछले दिनों आई दरार को मिटाने के लिए हो रही बयानबाजी के बीच गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली को लेकर भी किसान एकमत नहीं हैं। सिंघु पर आंदोलनरत कई किसान इस पक्ष में नहीं हैं कि राष्ट्रीय पर्व के दिन कोई भी ऐसी हरकत हो, जिससे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। इनका साफ कहना है कि हम ट्रैक्टर रैली किसी दूसरे दिन भी प्रस्तावित कर सकते हैं और सरकार तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहती है और इस दिन हम अपनी ताकत का अहसास कराते हैं। ऐसे में ट्रैक्टर रैली निकालने पर कहीं न कहीं इसका गलत संदेश दूसरे देशों में जाएगा। सिंघु बार्डर पर पंजाब से आए सुखवीर ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर यहां आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ वार्ता भी हो रही है। भले ही अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला हो, लेकिन दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक किसान संगठनों की ओर से

प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली की बात है तो मेरा मानना है कि कम से कम 26 जनवरी को इसे स्थगित किया जाना चाहिए। हमें दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि भले ही हमारे बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो, लेकिन जब बात देश की आएगी तो हमारी एकजुटता हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। पंजाब से आए परविंदर भी सुखवीर की बातों में हां में हां मिलाते हुए कहते हैं कि आंदोलन अपनी जगह है और गणतंत्र दिवस अपनी जगह। दोनों को एक साथ नहीं किया जाना चाहिए। तिलक नगर से सिंघु बार्डर पहुंचे राकेश कुमार ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहा आंदोलन कितना सही और कितना गलत है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन, प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर किसान संगठनों को विचार करने की जरूरत है। भले ही किसान संगठन शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली की बात कह रहे हैं, लेकिन यह न तो देश के लिए ठीक है और न ही आंदोलन के लिए। साथ ही आंदोलन के दौरान इस बात का जरूर खयाल रखा जाना चाहिए कि इससे किसी को परेशानी न हो। सिंघु बार्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब इससे परेशानी होनी शुरू हो गई है।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लड़खड़ाकर गिरा यात्री, तैनात सीआइएसएफ जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान

नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान की तत्परता से एक मेट्रो यात्री की जान बच गई। पूरा मामला 2 दिन पहले का है। सोमवार को डाबड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर यात्री अचानक अचेत हो गया था। जवान ने तुरंत उसे कार्डियो पल्मोनरी रीससिटेशन दिया, इससे सांस वापस आ गई और वह होश में आ गया। यात्री ने जान बचाने के लिए जवान को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सीआरपीएफ कर्मी ने किसी मेट्रो की जान बचाई है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की सेवाएं दी जा चुकी हैं। पूरे मामले को लेकर सीआइएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 18 जनवरी की सुबह जनकपुरी निवासी 45 वर्षीय सत्य नारायण मेट्रो यात्रा के लिए डाबड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे थे। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कर करीब नौ बजे जैसे ही वह सुरक्षा जांच प्वाइंट के समीप पहुंचे, वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े।

यह देखकर वहां मौजूद सीआइएसएफ के सिपाही विकास उनके पास पहुंचे। उन्होंने पाया कि यात्री की सांस लेने में तकलीफ रही है। गिरने से उनके मुंह और चेहरे पर भी चोटें भी आई थीं। स्थिति को भांपते हुए विकास ने तुरंत यात्री को सीपीआर देना शुरू किया। लिहाजा कुछ देर बाद सत्य नारायाण होश में आ गए। बाद में उन्हें स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं, बल के जवानों और स्टेशन कंट्रोलर ने यात्री को अस्पताल पहुंचाने के लिए सहायता की पेशकश की। लेकिन वे खुद की तबीयत बेहतर बताकर सिपाही को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। इससे पहले भी बल के जवान सीपीआर देकर कई यात्रियों की जान बचा चुके हैं। दरअसल दुर्घटना की स्थिति में सीपीआर देने से अमूमन शख्स की सांसें लौट आती है। सीआइएसएफ के सभी जवानों को सीपीआर देने का प्रशिक्षण दिया गया है।

दिल्ली में बर्ड फ्लू के 11 नए मामले, अब तक 1216 पक्षियों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में बर्ड फ्लू का असर भले ही कम हो गया है, मगर पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। मंगलवार तक दिल्ली में कुल 1216 पक्षियों की मौत हो चुकी है। अभी तक 158 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 46 की रिपोर्ट आ चुकी है। पोल्ट्री फार्म के मुर्गों की 35 रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि बतखों, कौओं, कबूतर व उल्लू मिलाकर अब तक 11 की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर मंगलवार की शाम तक 742 काल प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें अब अधिकतर काल करके लोग सलाह ले रहे हैं। जबकि पूर्व में कौओं आदि के मरने की शिकायतें अधिक आ रही थीं।

गौरतलब है कि दिल्ली में बर्ड फ्लू के मद्देनजर संजय झील पार्क,हस्तसाल पार्क और द्वारका के पार्क को बंद रखा गया है। वहीं, शनिवार को दिल्ली चिड़ियाघर में भी उल्लू और कबूतर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। संजय झील में बतखों और पूर्वी दिल्ली में ही स्थित मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में चार कौए की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इधर लाल किला परिसर से भेजे गए एक कौए के नमूने में बर्ड फ्लू मिला है। इसके बाद मंगलवार से लालकिला बंद कर दिया गया है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की निदेशक (स्मारक) अरविन मंजुल ने सोमवार देर शाम आदेश जारी कर दिए। जिसमें कहा गया है कि 19 जनवरी से बर्ड फ्लू के चलते और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लालकिला 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद रहेगा। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक डा राकेश सिंह के मुताबिक लाल किला परिसर में कुछ दिन पहले 15 कौवे मृत पाए गए थे। एक नमूने को जांच के लिए भोपाल और जालंधर भेजा गया गया था जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पशुपालन विभाग की टीम लगातार पार्कों में निगरानी बनाए हुए हैं और अधिक से अधिक नमूने इकट्ठा कर रही है।

26 जनवरी के बाद भी लाल किला को बंद रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए जिलाधिकारी संबंधित इलाके को संक्रमित घोषित कर बंद रखने के निर्देश जारी करेंगे।

ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन से आने वाले दिनों में ई-कॉमर्स में नौकरियों के अवसर में आएगी तेजी

कोरोना महामारी के कारण ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग को तवज्जो दिए जाने से पिछले एक साल में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोत्तरी देखी गई। मार्केट में सस्ते 4जी डेटा की उपलब्धता और नये शॉपिंग मॉडल्स से आए इस बदलाव के चलते ऑनलाइन खरीदारी यानी ई-शॉपिंग ने ई-कॉमर्स को तेजी से विस्तारित किया है।

देश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में दशहरा-दीपावली के त्योहारी सीजन में ई-प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदारी में पिछले वर्ष 2019 के त्योहारी सीजन की तुलना में लगभग 50 फीसद की बढ़ोत्तरी देखी गई। यही वजह है कि कोविड-19 के बीच वर्ष 2020 में देश भर में रोजगार घटने की चुनौतियों के बीच ई-कॉमर्स कंपनियां बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियां करते हुए भी दिखाई दीं। दुनिया की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का कहना है कि उसके द्वारा वर्ष 2025 तक भारत में दस लाख नये रोजगार के मौके सृजित किए जाएंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण के डर के बीच ऑनलाइन ही उत्पादों के कैटलॉग चेक करने और एक क्लिक पर सामान की डिलीवरी घर तक होने की सुविधा ने ई-शॉपिंग और ई-कॉमर्स को तेजी से बढ़ाया है। विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल डाटा एजेंसी स्टेटिस्टा द्वारा कोविड-19 के बाद जिंदगी में आए बदलावपर की गई स्टडी के मुताबिक, 46 फीसद लोगों का मानना है कि वे अब भीड़भाड़ में नहीं जाएंगे। भारत में भी उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार को देखते हुए ऑनलाइन खरीदारी छलांगे लगाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

भारत के ई-कॉमर्स बाजार की बात करें तो 27 फीसद सालाना की दर से बढ़ते हुए इस कारोबार के वर्ष 2024 तक 99 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स में आए बूम के कारण इस सेक्टर में डिलीवरी ब्वॉय से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग तथा फाइनेंस में प्रशिक्षित लोगों के लिए बड़ी संख्या में मौके लगातार सामने आ रहे हैं।

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में करियर बनाने की शुरुआत बारहवीं के बाद ही की जा सकती है। बारहवीं के बाद ई-कॉमर्स में सिंटफिकेट या वेब और ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी में सिंटफिकेट से लेकर बैचलर ऑफ ई-कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ई-कॉमर्स जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अलावा, स्नातकोत्तर स्तर के भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जैसे कि-एमबीए इन ई-कॉमर्स, मास्टर इन ई-कॉमर्स, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ई-कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस इन ई-कॉमर्स एप्लिकेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ई-कॉमर्स एप्लिकेशंस, पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट इन ई-कॉमर्स, एडवांस डिप्लोमा इन वेब ऐंड ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स एप्लिकेशन प्रोग्रामर, ई-कॉमर्स विजुअल एप्लिकेशन डेवलपर आदि। इसके अलावा, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से भी शॉर्टटर्म कोर्स किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ई-कॉमर्स की विशेषज्ञता के साथ-साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर दक्षता, निर्णय लेने की क्षमता, परिश्रम की प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन व टेक्निकल स्किल्स तथा जनसंचार से जुड़ी हुई स्किल्स लाभप्रद होती हैं। फिलहाल, देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों, विभिन्न शासकीय कॉलेजों और निजी क्षेत्र के कई संस्थानों में ई-कॉमर्स के सिंटफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

यमुना में प्रदूषण व अमोनिया की मात्रा कैसे होगी खत्म, विशेषज्ञ ने बताया उपाय

नई दिल्ली। यमुना में अमोनिया की मात्रा औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब है कि औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी सीधे यमुना में गिर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड पीने के पानी की आर्पूति के लिए यमुना से जिस जगह से पानी लेता है वह हिस्सा हरियाणा में आता है। ऐसे में यदि अमोनिया बढ़ने की वजह से जलार्पूति प्रभावित होती है तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए हरियाणा की तरफ से बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार है।

पानीपत, सोनीपत, करनाल समेत अन्य इलाकों से औद्योगिक इकाइयों से गंदा पानी सीधे नदी में गिर रहा है। इस वजह से दोनों राज्यों में तू-तू, मैं-मैं वाले हालात हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसे ही यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है जल बोर्ड द्वारा पानी की आर्पूति प्रभावित होने लगती है।

यह हर साल का मर्ज है। सर्दियों में यह समस्या थोड़ी भयावह हो जाती है क्योंकि हवा की गति कम हो जाती है। हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है। इससे पानी में आक्सीजन संबंधी प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, क्योंकि पानी में आक्सीजन की मात्रा शुद्धता का मापक है। स्वाभाविक है जब आक्सीजन की मात्रा कम होगी तो प्रदूषण बढ़ेगा ही। सर्दियों में यह बड़ा मसला हो जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। जिसमें एट्रलुऐंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, औद्योगिक इकाइयों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बनाने की बात कही गई। इसका मतलब

है कि औद्योगिक इकाई से कचराम और दूषित पानी निकलकर यमुना में ना गिरे। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा हो नहीं रहा है। इसका अंदाजा यमुना निगरानी समिति की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं।

रिपोर्ट इसी वर्ष 16 जनवरी को जारी की गई। जिसमें कहा गया है कि पानीपत के पास एक औद्योगिक इकाई है। कागज पर तो यह औद्योगिक इकाई जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है लेकिन जब अधिकारियों ने मौका मुआयना किया तो पाया कि इकाई की दीवार में एक बड़ा छेद है, जिससे दूषित पानी निकलता है और नदी में मिलता है। यह तो सिर्फ एक जगह की बात है। ऐसी स्थिति कई इलाकों में मिल जाएगी।

औद्योगिक इकाइयों से निकला दूषित पानी यमुना में जहर घोल रहा है। लाकडाउन में जब औद्योगिक इकाइयां बंद थीं तो यमुना का पानी साफ हो गया था। असल समस्या औद्योगिक कचरे से ही है, जिस पर अभी तक खास ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सीवेज तो अभी भी यमुना में गिर ही रहा है। औद्योगिक इकाइयों से यमुना में गिरने वाले कचरे पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। यही हाल हरनंदी का भी है। गाजियाबाद में औद्योगिक इकाइयों की भरमार है। कई कालोनियों में घर-घर काम होता है। इनसे जो दूषित पानी निकलता है वो नदी में गिरता है।

सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं बनेगी बात- यमुना का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। जब कोई सरकार यह कहती है कि किसी निश्चित समयसीमा में यमुना को स्वच्छ कर देगी तो उसे गंभीरता से इस पर अमल भी करना चाहिए। जब तक यमुना का अपना बहाव नहीं होगा तब तक नदी की स्थिति सही नहीं हो सकती है। सिर्फ एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर यमुना को साफ नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा संभव होता तो दिल्ली में 44 एसटीपी हैं। कुछ तो असर दिखना ही चाहिए। यमुना में प्रदूषण कम करने के लिए यमुना निगरानी समिति गठित की गई। लेकिन कमेटी को सिर्फ निगरानी का अधिकार है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो थोड़ा बहुत काम हुआ है उसमें यमुना निगरानी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। समिति ने एसटीपी बनाने, नाले सही करने, बहता हुआ पानी की व्यवस्था आदि पर निर्देश दिया है। बाढ़ क्षेत्र को लेकर कुछ काम धरातल पर नजर आता है। इसलिए कमेटी से कुछ आशा बनती है।

दिल्ली में अपने उच्चतर स्तर पर बना हुआ है पेट्रोल का दाम

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली-एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है। 85.20 रुपये प्रतिलीटर के साथ दिल्ली में पेट्रोल का दाम अपने उच्चतर स्तर पर है। वहीं, डीजल की कीमत दिल्ली में 75.38 रुपये प्रति लीटर है। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी इजाफा नहीं किया है। ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल 85.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल 75.38 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 26 और 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। इसके बाद लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 75.38 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 82.13 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिफ्ट की गई महात्मा गांधी की प्रतिमा

दिल्ली। संसद भवन में नए संसद भवन के निर्माण के लिए यहां लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को बुधवार को शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक ये मूर्ति संसद परिसर में गेट नंबर एक के पास लगी हुई थी। इसे अब यहां से हटाकर गेट नंबर 3 के पास शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त में 15 जनवरी के बाद से नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से 15 जनवरी से नई संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू करने को कहा था। नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुक्रवार से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग एक महीने पहले 10 दिसंबर को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा और इसके निर्माण को 2022 में आजादी के 75 वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने 2022 में संसद के

मानसून सत्र को नए भवन में आयोजित करने की योजना बनाई है। सूत्रों का कहना है कि टाटा प्रोजेक्ट्स ने अपने साजोसामान को निर्माणस्थल पर पहुंचाना पहले ही शुरू कर दिया था ताकि केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जल्द शुरू किया जा सके। विगत सोमवार को ही नए संसद भवन के निर्माण के लिए 14 सदस्यीय विरासत संरक्षण समिति ने अपनी मंजूरी दे दी थी। 971 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा किया जाना है। इस पूरी परियोजना को पूरा करने के लिए केवल दस महीने का ही समय है। योजना के मुताबिक, राजपथ के पुनर्विकास का काम इस साल गणतंत्र दिवस की परेड के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। 94 साल पहले महज 83 लाख रुपये में बने मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय बनाया जाएगा और उसके ठीक सामने नया संसद भवन बनेगा। सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण के बाद यह देश की सत्ता का गलियारा बन जाएगा। बता दें कि निर्माण कार्य पहले शुरू नहीं हो सका था, क्योंकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट ने 7 दिसंबर को नए संसद भवन के लिए आधारशिला रखने की अनुमति दी थी, लेकिन साथ में फैसला आने तक निर्माण न करने का आदेश दिया था। सरकार ने भी आश्वासन दिया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं का फैसला करने तक कोई निर्माण या विध्वंस कार्य शुरू नहीं होगा। कोर्ट ने पांच जनवरी को इस परियोजना को हरी झंडी दे दी थी और हेरिटेज कमिटी से मंजूरी लेने को कहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में, 14-सदस्यीय हेरिटेज पैनल ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने अमेजन प्राइम वीडियो को भेजा नोटिस, अपने प्लेटफॉर्म से हटाए तांडव

नई दिल्ली। डिंपल कपाड़िया और सैफ अली खान अभिनीत वेब सीरीज तांडव को लेकर देशभर में तांडव मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के बाद राजधानी दिल्ली में भी इसका विरोध तेज करने के साथ इस पर बैन लगाने की मांग की जाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने अमेजन प्राइम वीडियो को कानूनी नोटिस भेजकर मांग की गई है कि वेब सीरीज टांडवट को तुरंत उनके मंच से हटा दिया जाए, वरना उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की दिशा में कदम उठाया जाएगा। यहां पर बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान स्टारर हालिया रिलीज वेब सीरीज तांडव का देशभर में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इसके निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ मामला पुलिस तक पहुंच गया है। तांडव के निर्देशक पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी नई वेब सीरीज तांडव में हिन्दू देवी-देवताओं के अपमान करने के साथ जातिगत भावनाओं को भड़काने का काम किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ प्रयागराज में साधु-संतों समेत कई अन्य संगठनों ने वेब सीरीज के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ लखनऊ पुलिस द्वारा हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज तांडव को बनाने और रिलीज़ कराने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

बताया जा रहा है कि तांडव वेब सीरीज को रिलीज कराने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो की ओरिजनल कंटेंट हेड इंडिया अपर्णा पुरोहित, वेब सीरीज़ के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्णा मेहरा और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ नामजद और एक अन्य अज्ञात समेत 5 लोगों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

दिल्ली में आएंगी आसमानी रंग की बसें

नई दिल्ली। बसों के मामले में दिल्ली के लोगों को जल्द ही नए रंग की बसों का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली में अब आसमानी रंग की बसें भी दिखेंगी। जेबीएम आटो कंपनी की ये बसें डीटीसी की बेड़े में आएंगी। इससे पहले पिछले साल नीले रंग की एसी बस भी बसें आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जिन 1000 वातानुकूलित (एसी) बसें खरीदने के लिए आदेश जारी किया है, उनमें ये बसें भी शामिल हैं। ये बसें अप्रैल से आनी शुरू हो जाएंगी। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर अभी तक लाल, हरे व नारंगी व नीले रंग की चलती हैं। इसमें डीटीसी की एसी बसें अभी केवल लाल रंग की हैं और नान एसी बसें हरे रंग की हैं। इन बसों का बड़ी संख्या में 2009-2010 में आना शुरू हुआ था। वहीं नारंगी रंग की बसें क्लस्टर सेवा के तहत चलने वाली स्टेडर्ड फ्लोर की बसें हैं। ये बसें भी पिछले कई साल से दिल्ली में चल रही हैं। पिछले साल क्लस्टर सेवा के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस नीले रंग की लो फ्लोर एसी बसें आई हैं। अब इस साल जो 1000 एसी बसें आनी हैं। ये बसें बीएस-6 मानक पर आधारित हैं। इसमें 700 बसें ये बसें आसमानी, नीले व लाल रंग की भी होंगी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में आने वाली ये बसें एसी लो-फ्लोर सीएनजी बसें होंगी। आगामी वित्तीय वर्ष में जेबीएम ऑटो इन बसों की आपूर्ति करेगा। डीटीसी का दावा है कि यह बसें प्रतिवर्ष 50 मिलियन यात्रियों को परिवहन सेवा देगी और दिल्ली के लगभग 20 मार्गों को कवर करेंगी। डीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सभी बसें आधुनिक फीचर्स से लैस हैं। इनमें 4जी चिप, स्मार्ट कार्ड टिकटिंग सिस्टम, रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआइएस), इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस), आटोमेटिक बस व्हीकल लोकेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्टाप रिक्वेस्ट बटन, व्हीलचेयर रैंप आदि जैसी सुविधाएं होंगी। अधिकारी ने बताया कि ये बस यात्री के दरवाजे की ओर 60 एमएम झुकती हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और दिव्यांगों को चढ़ने और उतरने में सुविधा हो।

राम मंदिर निर्माण : निधि समर्पण अभियान के लिए कार्यालय का हुआ शुभारंभ

गुरुग्राम । अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बने इसके लिए एक से 27 फरवरी तक सुचारू रूप से निधि समर्पण अभियान चलाने के लिए बुधवार को गुरुद्वारा रोड स्थित श्री एसएन सिद्धेश्वर स्कूल में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ हवन आयोजित करके किया गया। हवन में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी स्वामी परमानंद की शिष्या महामंडलेश्वर साध्वी आत्मचेतना गिरी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की हरियाणा इकाई के प्रांत संघचालक पवन जिंदल सहित काफी संख्या में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

हवन के बाद शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर साध्वी आत्मचेतना गिरी ने कहा कि श्रीराम मंदिर के निर्माण से संतों का संकल्प पूरा हो रहा है। केवल मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि समरस समाज की ज्योति जागृत हो रही है। निश्चित ही इस मंदिर निर्माण से समाज में भगवान श्रीराम के आदर्श स्थापित होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरियाणा इकाई के प्रांत संघचालक पवन जिंदल ने कहा कि यह संपूर्ण समाज के लिए गौरव की बात है कि 492 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है।

मंदिर निर्माण में सर्व समाज की सहभागिता रहे इसलिए रामभक्त की टोलियां घर-घर जाकर सहयोग निधि एकत्रित करेंगी। प्रदेश में 12 हजार टोलियां लगभग 50 लाख घरों से संपर्क करेंगी। तीन करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा। जिले में निधि समर्पण अभियान के प्रमुख व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अजीत यादव एवं अभियान के सह प्रमुख संजीव सैनी ने बताया कि अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरुग्राम महानगर को 132 जोन में बांटा गया है।

इसमें 750 से अधिक टोलियों में लगभग तीन हजार कार्यकर्ता घर-घर जाकर श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि एकत्रित करेंगे। जिले में लगभग तीन लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समारोह में शेख सराय हनुमान मंदिर के महंत व निर्वाणी अखाड़े के कोतवाल स्वामी मुक्तानंद, न्यू कालोनी स्थित बाल्मीकि मंदिर के पुजारी हरिचंद, इस्कान मंदिर के संस्थापक सदस्य महेंद्र यादव, इस्कान मंदिर बादशाहपुर से कमल माधवदास ने भी अपने विचार रखे।

इस मौके पर आरएसएस के विभाग संघचालक प्रताप सिंह, महानगर संघचालक जगदीश ग्रोवर, विभाग कार्यवाह हरीश शर्मा, विभाग प्रचार प्रमुख अनिल कश्यप, विभाग संपर्क प्रमुख प्रदीप शर्मा, सिख संगत से हरजीत सिंह, राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत सह कार्यवाहिका प्रतिमा मनचंदा, इंदु जैन, मीनू शर्मा, रेणु गुप्ता, निर्मला यादव, सुजाता गौर, दीपा सिंह, रेणु पाठक, नगर निगम पार्षद सुभाष सिंगला, श्री एसएन सिद्धेश्वर मंदिर सभा के महासचिव रामअवतार गर्ग बिट्टू, कारसेवक ब्रह्म प्रकाश शर्मा, फिल्म अभिनेता राज चौहान, कल्याणी हस्पताल के निदेशक डा. सुभाष खन्ना, पूर्व वाइस चांसलर व शिक्षाविद् डा. अशोक दिवाकर, गो-सेवा आयोग के सदस्य पूर्णचंद लोहचब, निधि समर्पण अभियान के पालक अमन शर्मा, विमल शर्मा, टीएम शर्मा, सतपाल भारद्वाज, सोशल मीडिया प्रमुख गजेंद्र चौहान, अनुराग कुलश्रेष्ठ, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज, पाटलीपुत्र सांस्कृति चेतना समिति के महामंत्री संत कुमार, भाजपा नेता सुरेंद्र गहलोत एवं लोकेश मंगला आदि शामिल हुए।

संपादकीय

अपने वक्त के कुबेर और हकीकत

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो चुके हैं। उन्होंने एमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है। मतलब साफ है कि ऑनलाइन शॉपिंग से आगे का आइडिया बन चुकी है टेस्ला की बैटरी से चलने वाली कार। यानी अब टेस्ला का टाइम आ गया है। कुछ ही वर्ष पहले यह मजाक लगता था कि बैटरी से कार चलेगी, पर अब यह न सिर्फ असलियत है, बल्कि फिलहाल दुनिया का सबसे चमकदार आइडिया भी है। टेस्ला के शेयर में आए तेज उछाल की वजह से गुरुवार को एलन मस्क की कुल हैसियत 185 अरब डॉलर हो गई थी, जबकि उसी दिन बेजोस के शेयरों की कुल कीमत 184 अरब डॉलर ही थी। अगले दिन यानी शुक्रवार को भी टेस्ला में 7.84 प्रतिशत का उछाल दिखा, जबकि एमेजॉन में एक प्रतिशत से भी कम की बढ़ोतरी हुई। अर्थात अमीरों की सूची के पहले पायदान पर एलन मस्क की जगह और पक्की ही हुई।

यह किस्सा और चमत्कारी हो जाता है, जब आप देखें कि 2020 की शुरुआत में एलन मस्क दुनिया के पचास धनकुबरों की लिस्ट में भी मुश्किल से ही शामिल हो पाते। उस वक्त उनकी कुल हैसियत थी करीब 28 अरब डॉलर। उससे भी छह महीने पहले तो मस्क की कंपनी के बेतहाशा खर्च पर सवाल उठ रहे थे और उन्हें खुद अपने शेयर गिरवी रखकर मोटा कर्ज उठाना पड़ा था। दुनिया के इतिहास में वह सबसे तेजी से कुबेरों की सूची में टॉप पर पहुंचने वाले इंसान हैं। जुलाई में मस्क ने दिग्गज वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ा और सातवें नंबर पर पहुंचे। नवंबर के अंतिम सप्ताह में वह बिल गेट्स को भी पार कर दूसरे नंबर पर आ गए, और अब जनवरी की शुरुआत में वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं।

जिन लोगों को मस्क ने पीछे छोड़ दिया है, उनका हाल भी कुछ खास बुरा नहीं है। एक ऐसे दौर में, जब कोरोना महामारी और उससे पैदा हुआ आर्थिक संकट दुनिया के हर हिस्से में लाखों-करोड़ों लोगों के रोजगार, बचत और जीविका तक छीन चुका है, अमीरों की संपत्ति में हुई वृद्धि चौंकाने वाली है। एक अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक, कोरोना काल में ही सबसे अमीर 641 लोगों की हैसियत में एक लाख करोड़ डॉलर यानी सत्तर लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का इजाफा हुआ है। एक चौथाई हिस्सा तो इनमें से सिर्फ ऊपर के दस लोगों के हाथ लगा है। आप सोचते होंगे कि यह तो दूर देश की कहानी है, तो भारत का हाल भी कुछ खास अलग नहीं है। यहां भी इसी दौरान यानी कोरोना काल में देश के सात सबसे बड़े धन्ना सेठों की संपत्ति में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर, इन्होंने अपनी हैसियत में करीब 64 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की है। और यह हिसाब लगा था दिसंबर के बीच में। तब से अब तक बाजार में करीब साढ़े पांच प्रतिशत का उछाल और आ चुका है, तो यह आंकड़ा भी बढ़ चुका होगा। भारत में टॉप पर तो पिछले कुछ वर्षों से मुकेश अंबानी ही हैं, लेकिन इस बार वह दुनिया के दस बड़े सेठों की सूची से बाहर हैं। अब वह 13वें नंबर पर हैं। सबसे तगड़ी छलांग लगाई है गौतम अडानी ने। उनकी कुल संपत्ति करीब 29 अरब डॉलर की हो गई है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी है। संपत्ति बढ़ाने के मामले में अडानी इस साल दुनिया में नौवें नंबर पर रहे। उन्होंने हर रोज अपनी संपत्ति में करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये जोड़े हैं। उधर, चीन में जैक मा के गायब होने की खबर है। तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जैक मा दुनिया के व्यापार में चीन के दबदबे का एक बड़ा जरिया ही नहीं, दुनिया भर में चीन के पोस्टर बॉय भी थे। हुआ यह कि 24 अक्तूबर को जैक मा ने एक आयोजन में भाषण दिया और वहां चीन के बैंकिंग सिस्टम पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन के बैंक सूदखोर महाजनों की तरह काम कर रहे हैं और जमाने के साथ कदम मिलाकर नहीं चलते। उन्होंने बैंकिंग रेगुलेटर की भी आलोचना की। इस भाषण के बाद से जैक मा कहीं दिखाई नहीं पड़े हैं। उनकी कंपनी की जांच शुरू हो गई है और उनकी कंपनी एंट ग्रुप का आईपीओ भी सरकार ने रुकवा दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होता। चीन में बड़े व्यापारियों या उद्योगपतियों के गायब होने का यह पहला मामला नहीं है। ऐसे किस्से वहां होते रहते हैं।अक्तूबर में ही वहां एक और उद्योगपति ऐसे ही गायब हुए थे। कुछ समय बाद खबर मिली, भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें 18 साल की सजा सुना दी गई है। यह मामला इसलिए बड़ा और गंभीर है, क्योंकि यह वही जैक मा हैं, जिन्होंने दुनिया के रिटेल कारोबार में तहलका मचा रखा था। जिनकी सफलता दिखाकर भारत जैसे देशों में बहुत से उद्योगपति और उद्योग संगठन न सिर्फ चीन की तारीफ करते रहे हैं, बल्कि भारत में 'टू मच डेमोक्रेसी' होने की शिकायत भी। इधर भारत में शेयर बाजार उसी अंदाज में चल रहा है, मानो वह भारत का नहीं, चीन का बाजार हो। जीडीपी नीचे जाए, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, कोर सेक्टर में गिरावट से लेकर जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की सालाना गिरावट का अनुमान हो। ये सारी खबरें जैसे भारत के शेयर बाजारों के लिए मायने ही नहीं रखती हैं। इस चक्कर में हुआ यह कि इस धुआंधार तेजी के बावजूद भारत सरकार को टाटा समूह ने मात दे दी। बाजार में लिस्टेड सरकारी कंपनियों के शेयरों की कुल कीमत के मुकाबले टाटा समूह की लिस्टेड कंपनियों की कीमत कुछ ज्यादा हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के शेयर बाजार में सबसे बड़ी निवेशक भारत सरकार नहीं, बल्कि टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है। आज देशी-विदेशी निवेशक बाजार में जमकर पैसा झोंक रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब खासकर नए निवेशकों या छोटे निवेशकों को सावधान रहना चाहिए। जरूरी है कि हर कंपनी को ठोक बजाकर देखा जाए और आईपीओ में अर्जी लगाने के पहले पूरी पड़ताल की जाए। वरना साल भर से चल रहा यह दिवाली जैसा माहौल दिवालिया होने का कारण भी बन सकता है। सावधान रहें, कहीं आपका पैसा ही अमीरों की अमीरी और बढ़ाने में काम न आ जाए।

प्रवीण कुमार सिंह

देश की छवि बिगाड़ रहे फर्जी कॉल सेंटर, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं लग पाई कोई रोक

> देश का बैंकिंग सेक्टर भी साइबर ठगों के निशाने पर है। आज स्थिति यह है कि लगभग पूरे देश में रोजाना ही डेबिट कार्ड फ्रॉड की दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। कोई नहीं जानता कि एटीएम फ्रॉड, बीपीओ के जरिये देश-विदेश में ठगी, क्लोनिंग के जरिये क्रेडिट कार्ड से बिना जानकारी धन-निकासी और बड़ी कंपनियों के अकाउंट एवं वेबसाइट की हैकिंग और फिरौती वसूली की घटनाओं का यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा।

यह किसने सोचा था कि देश में जोरशोर से चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों का एक नतीजा इस रूप में निकलेगा कि टेक्नोलॉजी के जानकार कुछ लोग जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, लूट लेंगे। ये शब्द चुभ सकते हैं, देश के अभिमान को तोड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन दिनों देश में फर्जी कॉल सेंटरों के जरिये हो रहे गोरखधंधे की फेहरिस्त सामने आ रही है, उससे साबित हो रहा है कि इस फर्जीवाड़े पर तमाम कोशिशों के बावजूद कोई रोक नहीं लग पाई है। तथ्यों के मुताबिक गत साल देश में फर्जी कॉल सेंटरों से दुनिया भर के हजारों लोगों को ठगा गया। इसमें सबसे ज्यादा ठगी अमेरिकी नागरिकों से हुई। करीब 20 हजार अमेरिकियों को इस किस्म के फर्जीवाड़े का शिकार बनाया गया। इस दौरान फर्जी कॉल सेंटरों से करीब 400 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई। ठगी का यह सिलसिला नया नहीं है, बल्कि बीते करीब पांच वर्षों से ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं।

एक तोहमत झारखंड के जामताड़ा पर लगती रही है कि यह स्थान दुनिया भर के साइबर क्राइम का गढ़ है, लेकिन अब साबित हो रहा है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से लेकर कई छोटे कस्बों में बैठे आइटी के जानकार युवा भी इसमें पीछे नहीं हैं। यदि बात देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके की हो तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने बीते साल यहां सबसे ज्यादा 20 से अधिक फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया। इनमें से पांच काफी बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे थे, जिनमें से हरेक में 30 से ज्यादा युवा काम कर रहे थे। साइबर क्राइम यूनिट ने इन फर्जी कॉल सेंटरों के संचालन में एक बड़े अंतर का भी पता लगाया है। पुलिस के मुताबिक पहले ऐसे ज्यादातर मामलों में किसी कॉल सेंटर में काम करने वाला पूरा स्टाफ

फर्जीवाड़े में शामिल नहीं होता था। केवल इसके संचालक ही ऐसा करते थे और कुछ युवाओं से यह काम कराते थे, लेकिन अब इन फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने वाले सभी स्टाफ को यह बखूबी पता होता है कि वे विदेशियों को तरह-तरह से भयभीत करते हुए उनसे ठगी कर रहे हैं। एक और उल्लेखनीय बदलाव यह पता चला है कि फर्जी कॉल सेंटरों के पकड़े जाने की खबरें पढ़कर ही इन युवाओं के दिमाग में इस तरह से रातोंरात अमीर बनने का विचार आता है और वे आगा-पीछा सोचे बगैर इस धंधे में शामिल हो जाते हैं। इन घटनाओं को देखकर हरेक के मन में यह सवाल उठता है कि क्या यही हमारे देश की डिजिटल साक्षरता का हासिल है? क्या ऐसे ही साइबर क्राइम करने के लिए हमारे कुछ नौजवान आइटी की शिक्षा हासिल कर रहे हैं? वे लालची हैं या फिर कहीं बेरोजगारी से परेशान होकर उन्होंने साइबर ठगी का यह रास्ता अख्तियार कर लिया है?

बीते वर्षों में घटित मामलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले कुछ अर्से से प्रायः हर साल हमारे देश में साइबर क्राइम का कोई न कोई नया रूप सामने आ रहा है। इन मामलों पर अक्सर नजर तभी जाती है, जब कोई बड़ा मामला पकड़ में आता है। जैसे तीन साल पहले वर्ष 2017 में नोएडा में सिर्फ तीन लोगों ने इंटरनेट पर एक पोंजी स्कीम बनाकर सैकड़ों पढ़े-लिखे लोगों को 37 अरब रुपये का चूना लगा दिया था। ऑनलाइन ठगी का यह एक कीर्तिमान था, क्योंकि इससे पहले देश में इतने बड़े पैमाने पर कोई साइबर घोटाला नहीं हुआ था। वर्ष 2018 में तीन दर्जन लोगों ने इससे भी बड़ा हाथ मारने की कोशिश की। इन लोगों ने इंटरनेट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर के जरिये करीब 15 देशों के 50 हजार लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूट लिया। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ, जब अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआइ), इंटरपोल और कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने गुरुग्राम और नोएडा पुलिस को मामलों की जांच को कहा और इसमें दोनों शहरों के 17 फर्जी कॉल सेंटरों से 42 लोगों की धरपकड़ हुई। इनमें से आठ कॉल सेंटर गुरुग्राम के थे। जबकि नौ नोएडा के। इन लोगों द्वारा की गई साइबर ठगी की जानकारी माइक्रोसॉफ्ट को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 15 देशों के लोगों की शिकायत के जरिये मिली थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर उनके कंप्यूटरों में मालवेयर (एक तरह के कंप्यूटर वायरस) भेज देते हैं और फिर उन्हें निकालने के नाम पर माइक्रोसॉफ्ट का हवाला देकर सौ से एक हजार अमेरिकी डॉलर तक ऐंठ लेते हैं। फर्जी कॉल सेंटरों के रूप में किए जा रहे साइबर फर्जीवाड़े की घटनाओं से यह विचार करने की जरूरत पैदा हुई है कि आखिर जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग साइबर ठगों के जाल में फंसने से बच क्यों नहीं पा रहे हैं और क्यों ऐसे मामले बिल्कुल शुरुआत में पकड़ में नहीं आ पाते हैं? इंटरनेट के प्रचार-प्रसार का दौर शुरू होने के बाद से यह लगातार कहा जाता रहा है कि भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती साइबर आपराधिक गतिविधियां ही होंगी। यानी इंटरनेट के माध्यम से संचालित की जाने वाली वे आपराधिक और आतंकी गतिविधियां जिनसे कोई व्यक्ति या संगठन देश-दुनिया और समाज को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे। अभी तक देश में इस तरीके से कई गैरकानूनी काम हुए हैं, जैसे ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग नेटवर्क में सेंधमारी, गलत प्रोफाइल बनाकर लोगों-खासकर महिलाओं को परेशान करना आदि, लेकिन अब इसमें सोशल नेटवर्किंग के जरिये एक किस्म की पोंजी स्कीम चलाना और फर्जी कॉल सेंटरों से पूरी दुनिया के लोगों को ठगना भी जुड़ गए हैं। इसमें शक नहीं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ठगी के दर्जनों तरीके हैं जिनके जरिये लोगों को फंसाया जाता है और उनसे रकम ऐंठी जाती हैं। लॉटरी का झांसा देना, किसी दूसरे मुल्क में वसीयत में छोड़ी गई संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर करने के बदले फीस मांगना, विदेश से आए तोहफे की ड्यूटी चुका उसे आप तक पहुंचाना, क्रेडिट-डेबिट कार्ड की हैकिंग जैसी अनगिनत वारदातें तकरीबन रोज होती हैं। और एक किस्सा बंद होते ही साइबर ठगी का कोई दूसरा नया उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसे हादसे साबित करते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में सजगता का सारा मामला एकतरफा है। यानी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो सीख गए हैं, पर उसके विभिन्न मंचों पर क्या-क्या सावधानियां बरतें-इसका उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। सरकार भी कानून पर कानून तो बनाती रहती है, पर उसके पहरुओं की नींद भी तभी टूटती है जब करोड़ों का घोटाला हो चुका होता है और लाखों लोग अपनी पूंजी गंवा चुके होते हैं।

देश का बैंकिंग सेक्टर भी साइबर ठगों के निशाने पर है। आज स्थिति यह है कि लगभग पूरे देश में रोजाना ही डेबिट कार्ड फ्रॉड की दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। कोई नहीं जानता कि एटीएम फ्रॉड, बीपीओ के जरिये देश-विदेश में ठगी, क्लोनिंग के जरिये क्रेडिट कार्ड से बिना जानकारी धन-निकासी और बड़ी कंपनियों के अकाउंट एवं वेबसाइट की हैकिंग और फिरौती वसूली की घटनाओं का यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा।

ब्रह्मपुत्र पर बांध का चीन भारत के खिलाफ वाटर-बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है

उर्दू के मशहूर शायर मुजफ्फर इस्लाम रज्मी का एक शेर है-'ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।' इसे अगर भारत-चीन रिश्तों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद शायद ही कुछ कहने को बचेगा। 1951 में भारत ने जिस तरह से आंख मूंदकर चीन को तिब्बत पर आराम से कब्जा करने दिया उसके बाद पिछले सत्तर वर्षों में एक भी दिन नहीं बीता जब भारत ने इस गलती की सजा न भुगती हो। इस भयंकर भूल के बाद चीन की सेना आसानी से तिब्बत को लांघकर भारत की हिमालयी सीमा पर आ धमकी। तबसे उसने भारत के खिलाफ जैसी खुराफातों का सिलसिला शुरू किया उसकी फेहरिस्त अंतहीन है।

तिब्बत को आधार बनाकर डोकलाम, अरुणाचल और लद्दाख में चीन की दादागीरी अभी चल ही रही है। इस बीच चीन ने भारत के खिलाफ एक नई तरह के हमले का बिगुल बजा दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा की है कि चीन तिब्बत की नदी यारलुंग सांगपो (भारतीय नाम 'ब्रह्मपुत्र') पर भारत की सीमा से ठीक 30 किलोमीटर पहले एक 'सुपर डैम' बनाने जा रहा है, जिसकी क्षमता चीन और दुनिया के सबसे बड़े डैम 'थ्री गॉर्जेस डैम' से भी तीन गुनी होगी। इस पर संभावित खर्च का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में र्निमित थ्री गॉर्जेस डैम की बिजली क्षमता 22.5 गीगा वाट थी और इस पर 31.7 अरब डॉलर (लगभग 2300 अरब रुपये) खर्च हुए थे। तिब्बत के अंतिम छोर पर प्रस्तावित नए डैम को अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इसकी बिजली उत्पादन क्षमता भाखड़ा नंगल डैम से 111 गुना और भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना टिहरी डैम के मुकाबले 27 गुना अधिक होगी। यानी यह चीनी परियोजना भारत की सबसे बड़ी पांच पनबिजली परियोजनाओं की कुल क्षमता से भी नौ गुना अधिक होगी। चीन इस इलाके में अभी ऐसी दो और परियोजनाओं के लिए भी तैयारी कर रहा है। चीन की इस घोषणा ने भारत के लिए बहुत गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस परियोजना के लिए चीन जितने बड़े पैमाने पर बांध बनाने जा रहा है वह ब्रह्मपुत्र के बहाव को बहुत प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर अरुणाचल प्रदेश और असम की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर होगा। इसका प्रभाव भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह नदी भारत के बाद बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस 'सुपर डैम' परियोजना ने भारत के लिए इस सबसे कहीं ज्यादा बड़ा एक जोखिम और भी बढ़ा दिया है। वह यह कि भारत की सीमा के इतने करीब पानी की इतनी विशाल मात्रा को वह भारत के खिलाफ कभी भी एक 'वाटर-बम' की तरह इस्तेमाल करके असम और अरुणाचल में भयंकर तबाही मचा सकता है। ऐसा हमला भारत की नागरिक आबादी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए और विशेष रूप से वहां रक्षा तंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से खतरे की घंटी है।

चीन के इस 'वाटर-बम' का खतरा कोरी कल्पना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कम से कम तीन अवसर आ चुके हैं जब चीन ने जानबूझकर ऐसे नाजुक मौकों पर भारत की ओर नदियों का पानी छोड़ा जिसने भारत में भारी तबाही मचाई। जून 2000 में अरुणाचल के उस पार तिब्बती क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर बने एक डैम का एक हिस्सा अचानक टूट गया जिसने भारतीय क्षेत्र में घुसकर भारी तबाही मचाई। उसके बाद जब भारत के केंद्रीय जल शक्ति आयोग ने इससे जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया तो पाया गया कि चीनी बांध का टूटना एक पूर्वनियोजित शरारत थी। उस घटना के कुछ सप्ताह बाद ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भी ठीक ऐसी ही घटना हुई। तिब्बत की ओर से जो पानी अचानक छोड़ा गया उसकी पहली लहर ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसकी ऊंचाई 50 फुट तक थी। उस बाढ़ ने किन्नौर के इलाके में 200 किलोमीटर भीतर तक कहर ढाया। इसी तरह की तीसरी घटना 2005 की पारीचू नदी से संबंधित है। उस समय बाढ़ के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने चीन से इस पानी के बारे में ताजा आंकड़े साझा करने और भारतीय इंजीनियरों की एक टीम को तब तिब्बत में बनी कृत्रिम झील का मुआयना करने की अनुमति मांगी, लेकिन चीन सरकार ने न तो आंकड़े जारी किए और न भारतीय विशेषज्ञों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति दी। रक्षा विशेषज्ञों की चिंता है कि यदि भारत के साथ युद्ध की हालत में या किसी राजनीतिक विवाद में चीन ने ब्रह्मपुत्र पर बनाए गए बांधों के पानी को 'वाटर-बम' की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया तो भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में जानमाल और रक्षा तंत्र के लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगा।

इसके अलावा चीन एक और षड्यंत्रकारी योजना पर काम कर रहा है। वह है इस डैम से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करके पंपों और नहरों की मदद से ब्रह्मपुत्र के पानी को चीन के दूर वाले इलाकों की ओर मोड़ देना। इस तरह की कुछ और योजनाओं पर भी चीन पहले से काम कर रहा है जिनका लक्ष्य वहां से निकलने वाली दूसरी कई नदियों के पानी को अपने उन इलाकों की ओर मोड़ देना है जहां पानी की कमी है। इन योजनाओं का सीधा असर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम समेत दस देशों पर पड़ेगा। इनमें से अधिकांश देश चीन की इस दादागीरी से परेशान हैं। अब सवाल उठता है कि भारत इन देशों के साथ चीन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का साहस कब जुटा पाता है?

टीआरपी घोटाले की रेंज

मुंबई पुलिस द्वारा उजागर किया गया टीआरपी घोटाला शुरू में सीमित महत्व का ही माना जा रहा था, लेकिन ब्यौरे उजागर होने के साथ यह विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। बीते सप्ताह मुंबई पुलिस की ओर से फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बतौर सबूत शामिल किए गए वॉट्सऐप चैट सामने आने से इस प्रकरण के साजिश वाले पहलू अचानक बेहद गंभीर हो गए। हालांकि अभी इस मामले में जांच चल ही रही है। पुलिस द्वारा जुटाए गए तमाम सबूतों का अदालत में परीक्षण होना बाकी है लेकिन जो साक्ष्य अब तक सामने आए हैं वे इतना तो बताते ही हैं कि इस मामले को महज बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल) के स्तर पर होने वाली गड़बड़ी के रूप में नहीं समझा जा सकता। साफ लगता है कि एक खास चैनल की तरफ से उसको फायदा पहुंचाने के लिए बीएआरसी में अहम पदों पर बैठे कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इसमें अति संवेदनशील मुद्दे पर अग्रिम जानकारी साझा की गई है, जो स्वयं में एक स्वतंत्र जांच का मुद्दा होना चाहिए। कोई चैनल या पत्रकार खुद को नंबर वन दिखाने के लिए सत्ता में अपनी पहुंच का कैसा इस्तेमाल कर सकता है, यह तो इससे साफ होता ही है, साथ ही यह सवाल भी उठने लगता है कि सत्ता में अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए वह खबरों के साथ कैसा खिलवाड़ करता होगा। पत्रकार और मीडिया के साथ प्रामाणिकता की जो शर्त जुड़ी हुई है, उसकी अगर एक मामले में धज्जियां उड़ाते आप दिख जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके सारे काम संदेह के घेरे में आ जाते हैं।

ये वॉट्सऐप चैट अगर सही हैं तो कहना ही होगा कि मामले का मुख्य आरोपी या कथित मास्टरमाइंड बीएआरसी में बैठा शख्स नहीं बल्कि चैनल के ऑफिस से उसे निर्देशित करने वाला व्यक्ति है। बीएआरसी के संबंधित अधिकारी पर अधिक से अधिक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए पद के दुरुपयोग का मामला बनता है, लेकिन चैनल संचालकों पर न केवल विज्ञापनदाताओं के साथ बेईमानी और बाकी चैनलों के साथ धोखाधड़ी करने का बल्कि दर्शकों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप चस्पां होता है। इसके अलावा सत्ता से नजदीकी के गलत इस्तेमाल का सवाल अपनी जगह है।

इस चैनल की रिपोर्टिंग को लेकर जितनी शिकायतें की जाती रही हैं, ताजा प्रकरण के बाद क्या उन सबको पत्रकारीय विवेक की स्वतंत्रता का हवाला देकर दरकिनार किया जा सकेगा? बात जहां तक कानूनी प्रक्रिया की है तो उसे अपने तय रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कि इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट न आए और किसी संदेह या अविश्वास के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए। मीडिया के आत्म अनुशासन का रास्ता भी ऐसे विचलनों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए ही तैयार हो पाएगा, इनकी अनदेखी करके नहीं।

कोरोना वैक्सीन में विज्ञानियों की मेहनत नहीं, बल्कि भाजपा का अक्स दिखता

> असल में विपक्षी दलों की पूरी आस इसी पर टिकी है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता न होने पाए। विपक्ष की हालत यह हो गई है कि समस्या के समाधान में उसकी रुचि नहीं रह गई है। वह समाधान में समस्या खोजता है। उसे समस्या में ही अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है। इसीलिए किसानों के मसले का हल नहीं निकल रहा है और न ही निकलने के आसार दिखते हैं। बात सरकार तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस आधार पर सही गलत ठहराया जाता है कि वह सरकार के विरोध में जाता है या पक्ष में।

भारतीय राजनीति एक विचित्र दौर से गुजर रही है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सार्थक संवाद की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। असल में संवाद के लिए जरूरी है कि बात तर्कों और तथ्यों के आधार पर हो। तर्क और तथ्य के बिना बनाई गई धारणा के आधार पर अव्वल तो बहस मुश्किल है और हो भी जाए बेनतीजा ही रहती है। यही वजह है कि किसानों से बातचीत 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' की गति को प्राप्त हो रही है। यह काफी नहीं था कि अब कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तरीका वही कि जिनको विषय की जानकारी नहीं वही विशेषज्ञ बने घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में कोई सत्तारूढ़ दल पहली बार इतना ताकतवर हुआ है। कांग्रेस का लंबे समय तक देश पर एकछत्र राज था। केरल में पहली वामपंथी सरकार बनी तो बहुमत होते हुए भी उसे बर्खास्त कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया उतना अन्य दलों की सभी सरकारें मिलकर भी नहीं कर सकीं। कांग्रेस की विपक्ष के प्रति सदाशयता की स्थिति यह रही कि आजादी के तीन दशक बाद तक उसने विपक्षी दल को नेता-प्रतिपक्ष का पद ही नहीं दिया। 1977 में पहली बार देश को लोकसभा में विपक्ष का नेता मिला। वह भी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार में। हालांकि जब 2014 में कांग्रेस के पास नेता-प्रतिपक्ष पद के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था तो उसके लिए अचानक सहानुभूति उपजने लगी। कहा जाने लगा कि भाजपा में जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदना नहीं

है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस से दरियादिली ही दिखाई।

भाजपा के लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाते ही राजनीति ही नहीं देशनीति के सारे नियम बदल गए। आजादी के बाद से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में एक अघोषित समझौता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश एक स्वर में बोलेगा। ऐसा नहीं है कि तब विपक्षी दल इन मुद्दों पर सरकार की आलोचना या विरोध नहीं करते थे। बस उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा का अहसास था। लक्ष्मण रेखा यह थी कि विपक्ष इन मुद्दों पर ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे देश के विरोधी उसका लाभ उठा सकें। संकट के समय पूरा देश एक स्वर में बोलता था। अब ऐसा नहीं है। अब देश के दुश्मनों और कुछ विपक्षी दलों की भाषा एक ही होती है। पिछले छह-सात वर्षों में ही यह बदलाव आया है। अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा बदलाव देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस में आया है। उसने अपनी पुरानी स्लेट साफ कर दी है।

कांग्रेस में नई इबारत वही लिख रहे हैं जिन्हें न तो राजनीति की समझ है और न ही राष्ट्रीय मुद्दों की गंभीरता का अहसास। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सही लिखा है कि उनके राष्ट्रपति भवन जाने के बाद कांग्रेस को राजनीतिक दिशा देने वाला कोई नहीं रह गया। दस साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह कभी नौकरशाह वाली मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए। देश उनकी रीढ़ खोजता रहा, पर वह मिली नहीं। फिलहाल कांग्रेस ट्विटर की पार्टी बनकर गई है।

विपक्ष में केवल कांग्रेस ही दिशाहीन नहीं है। उसमें अखिलेश यादव जैसे नेता भी हैं। उन्हें कोरोना वैक्सीन में देसी विज्ञानियों की मेहनत नहीं, बल्कि भाजपा का अक्स दिखता है। यह तो सरकार का विरोध भी नहीं है। इसे दिमागी दिवालियेपन का सुबूत ही माना जा सकता है। कांग्रेस में भी शशि थरूर, आनंद शर्मा और जयराम रमेश जैसे नेताओं के वैक्सीन से जुड़े बयानों से यही लगता है कि उन्हें इसे बनाने वाले विज्ञानियों से ज्यादा जानकारी है। भारत ने दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। देश के लिए यह गर्व की बात है। कोविशील्ड का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है जबकि कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। इसी आधार पर उसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। उसी को लेकर विपक्ष दुष्प्रचार में लगा है जबकि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी के वैज्ञानिक, आइसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन जैसे दिग्गजों को कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव पर कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं कोरोना के जिस नए रूप से इन दिनों यूरोप सहमा हुआ है, उस पर भी भारतीय वैक्सीन प्रभावी होगी।

दरअसल अंध विरोध करने वाले भूल जाते हैं कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसे वैक्सीन बनाने और लगाने का इतना वृहद अनुभव है। ऐसे में दवा और शोध के बारे में विज्ञानियों की बात पर भरोसा किया जाए या नेताओं की बात पर। विज्ञानियों को वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने का यकीन है, लेकिन विपक्षी नेताओं को नहीं। उन्हें यह भी अहसास नहीं है कि इस उपलब्धि पर सवाल उठाकर वे सरकार या प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि विज्ञानियों का ही अपमान कर रहे हैं।

दरअसल इसकी आड़ में उनके निशाने पर एक ही व्यक्ति है-नरेंद्र मोदी। मोदी के राज में कुछ अच्छा हो तो विपक्ष की समस्या बढ़ जाती है। खराब हो तो खुशी की बात है। वह देश के लिए अच्छी है या नहीं इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। यही कारण है कि पिछले छह वर्षों से अदाणी-अंबानी को देश का पाकिस्तान और चीन से बड़ा शत्रु साबित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। देश का गरीब आदमी जानता और मानता है कि मोदी सरकार उनके हित में काम कर रही है, मगर विपक्षी दलों का एक समूह देश को बरगलाने में जुटा है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। अन्यथा क्या वजह थी कि जो आंदोलन किसानों के नाम पर किया जा रहा है उसकी आड़ में रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाया जाता जिसका खेती-किसानी से कोई लेनादेना ही नहीं। असल में विपक्षी दलों की पूरी आस इसी पर टिकी है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता न होने पाए। विपक्ष की हालत यह हो गई है कि समस्या के समाधान में उसकी रुचि नहीं रह गई है। वह समाधान में समस्या खोजता है। उसे समस्या में ही अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है। इसीलिए किसानों के मसले का हल नहीं निकल रहा है और न ही निकलने के आसार दिखते हैं। बात सरकार तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस आधार पर सही गलत ठहराया जाता है कि वह सरकार के विरोध में जाता है या पक्ष में।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

माता वैष्णो देवी जा रहा युवक पठानकोट में हुआ दर्दनाक हादसे का शिकार, ट्रेन से यात्रा में न करें ऐसी गलती

पठानकोट । यदि ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो ऐसी गलती कभी न करें जैसी यहां एक युवक ने की। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे यह युवक पठानकोट में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। वह चलती ट्रेन से उतरकर मोबाइल उठाने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रहने वाला था। वह यात्रा के दौरान ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था और इसी दौरान उसका मोबाइल फोन हाथ से छूट की नीचे गिर गया। ट्रेन की रफ्तार कम होने की जगह से उसने नीचे उतर कर मोबाइल उठाने की कोशिश की और इस दौरान ट्रेन से कट गया। युवक की पहचान 25 वर्षीय प्रशांत कुमार पुछ्वाहा के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गांव रावतपुर का रहनेवाला था। जानकारी के अनुसार, प्रशांत कुमार अपने 12 दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए संबलपुर एक्सप्रेस से जम्मू जा रहा था। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि प्रशांत मोबाइल फोन लेकर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। ट्रेन पठानकोट कैंट स्टेशन पर पहुंचने वाली थी जिस कारण गति कुछ कम थी। इस बीच प्रशांत का मोबाइल फोन उसके हाथों से नीचे गिर गया। ट्रेन की गति कम होने के कारण वह सीढ़ियों से नीचे उतर मोबाइल पकड़ने की कोशिश करने लगा था कि उसका पैर सीढ़ियों में फंस गया। ट्रेन की चपेट में आने से प्रशांत की दोनों टांगें व एक बाजू कट गई।

जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) ने घायल अवस्था में प्रशांत को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। अस्पताल मेंउपचार दौरान उसकी मौत हो गई। जीआरपी पठानकोट कैंट चौकी प्रभारी एएसआइ पलविंद्र सिंह ने बताया कि युवक के शव का पठानकोट के सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और स्वजनों को सौंप दिया गया।

उत्तराखंड में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा- गरीबों का निवाला छीन रही केंद्र और राज्य सरकार

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाकर सभी जिला और शहर मुख्यालयों में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है। जगह-जगह सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। उनका कहना है कि सरकार ऐसा कर गरीबों का निवाला छीनने का काम कर रही है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदेशभर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर नारेबाजी की। विकासनगर में कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। बढ़ती महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी विकासनगर ने पहाड़ी गली चौक पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जिलाध्यक्ष संजय किशोर और शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश ने कहा कि महंगाई बढ़ाकर सरकार ने आमजन का निवाला छीनने का काम किया है। हरिद्वार जिले के रुड़की में महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से महंगाई चरम पर है और डीजल-पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं रसोई गैस भी दो गुना महंगी हो गई है। सरकार को आम जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। इस मौके पर पूर्व गृह राज्य मंत्री राम सिंह सैनी, पूर्व महापौर यशपाल राणा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश संगठन सचिव विकास त्यागी, दिनेश कौशिक, नगर अध्यक्ष कलीम खान, राजेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड में कार्मिकों की कमी से जूझ रही परिवहन विभाग की चेकपोस्ट, 19 में से सिर्फ 13 ही सक्रिय

देहरादून । उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में एंट्री टैक्स (प्रवेश शुल्क) लेने के लिए बनाई गई चेकपोस्ट पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रही हैं। स्थिति यह है कि विभाग में स्वीकृत 19 चेकपोस्ट में से केवल 13 ही सक्रिय हैं। शेष छह फिलहाल बंद चल रही है। इतना ही नहीं इन सभी को कंप्यूटरीकृत करने की मंशा भी परवान नहीं चढ़ पाई है। प्रदेश में आने वाले विभिन्न मार्गों में एंट्री टैक्स वसूलने के लिए परिवहन महकमे ने जगह-जगह चेकपोस्ट बनाई हुई हैं। इन चेकपोस्टों से विभाग चार करोड़ रुपये से अधिक की सालाना कमाई करता है। वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों से प्रवेश शुल्क लेने का निर्णय लिया था। इसके लिए बाकायदा राशि भी तय की गई थी, पर कर्मचारियों की कमी इसका रोड़ा बन रही थी। चेकपोस्टों पर अवैध वसूली की शिकायतें भी विभाग के लिए एक परेशानी बन रही थी। ऐसे में विभाग ने निजी कंपनियों के जरिये इस काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह कार्य रुक गया।

इतना ही नहीं विभाग ने चेकपोस्टों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया, लेकिन यह काम भी आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे में विभाग ने बाहर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से शत प्रतिशत शुल्क वसूलने के लिए इन चेकपोस्टों को हाईटेक करने की योजना बनाई। इसके तहत हर चेकपोस्ट पर एक कंप्यूटर लगाने के साथ ही इसमें नए सॉफ्टेयर डाल कर इन्हें परिवहन मुख्यालय से सीधे जोड़ने की थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपकरणों का भी प्राविधान किया गया। इसमें भी कुछ ही चेकपोस्टों पर यह व्यवस्था हो पाई। इसके बाद शुल्क ऑनलाइन लिए जाने की व्यवस्था बनी। इसके साथ ही चेकपोस्टों की संख्या सीमित करने की बात हुई। इस बीच फर्जी रसीद का मामला सामने आने के कारण चेकपोस्टों को फिर से सक्रिय कर दिया गया। हालांकि, कर्मचारियों की कमी के चलते मात्र 13 चेकपोस्ट ही अभी सक्रिय रूप से चल रही हैं। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभाग की मंशा निकट भविष्य में इन्हें कम करने की भी है।

रांची के रिम्स में जिसको मन उसको दे दिया कोरोना टीका, सारे नियम हवा में...

रांची । स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में कोरोना टीकाकरण के क्रम में नियम तोडने को गंभीरता से लिया है। विभाग के प्रधान सचिव डा. नितिन मदन कुलकर्णी ने इसे लेकर रिम्स के निदेशक डा. कामेश्वर प्रसाद को पत्र लिखकर पूछा है कि किस परिस्थिति में कोविन पोर्टल पर निबंधन तथा सूची में नाम नहीं होने के बावजूद कुछ चिकित्सकों को कोरोना टीका लगाया गया। उन्होंने नियम तोडनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों की पहचान कर जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।

दरअसल, रिम्स में सोमवार को टीका लेनेवाले की सूची में नाम शामिल नहीं होने के बावजूद संस्थान के अधीक्षक डा. विवेक कश्यप तथा कई अन्य चिकित्सकों को कोरोना का टीका लगा दिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने इसपर काफी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि कोरोना का टीका उसे ही लग सकता है जिसका नाम कोविन पोर्टल पर निर्बंधित है। साथ ही जिला प्रशासन की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा केंद्र को नाम भेजे जाते हैं, जिनसे सौ-सौ लोगों का रैंडम चयन एक दिन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इसके बाद चयनित लाभुकों को टीकाकरण का मैसेज भेजा जाता है तथा अगले दिन संबंधित अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण का सत्र आयोजित होता है। टीकाकरण से पहले भी कोविन पोर्टल पर लाभुकों के डाटा का मिलान किया जाता है तथा उससे पहचान प्रमाणपत्र भी लिए जाते हैं। इसके बाद ही टीकाकरण की अनुमति मिलती है। रिम्स में टीकाकरण के पहले दिन अधीक्षक व कुछ अन्य चिकित्सकों के मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन भी मंगलवार को लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 56 फीसद स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीके लगे। तीसरे दिन राज्य के विभिन्न जिले में कुल 2,735 लोगों को टीके लगे, जबकि 48 केंद्रों पर 4,892 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य था। राज्य में तीन दिनों के अभियान में अबतक कुल 8,795 को पहली डोज लग चुकी है। बताया जाता है कि टीकाकरण के लिए एक दिन पहले मैसेज भेजे जाने से परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को समय पर मैसेज नहीं मिल पा रहा है।

गाड़ी पलटने पर पिस्टल लूटकर भागने में मारा गया था विकास दुबे, पुलिस को मिली क्लीन चिट

कानपुर । बिकरू कांड में आरोपित दुर्दांत हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे और सहयोगियों के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सभी सवालों पर विराम लग गया है। मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय रास्ते में गाड़ी पलटने पर पुलिस कर्मी की पिस्टल लूटकर भागते समय विकास दुबे एनकाउंटर में ही मारा गया था। जिला प्रशासन के आदेश पर हुई मजिस्ट्रेटी जांच में सभी एनकाउंटर सही माने गए हैं और पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की बात कही है।

2 जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद दूसरे दिन विकास के दो साथियों अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडेय को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद हमीरपुर में अमर दुबे और पनकी इलाके में प्रभात पांडेय एनकाउंटर में मारा गया था। इसी तरह इटावा में भी बिकरू कांड में फरार बदमाश मारा गया था। वहीं मध्य प्रदेश में पकड़े गए विकास दुबे को कानपुर लाते समय सचेंडी के पास गाड़ी पलट गई थी। हादसे के बाद इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की पिस्टल लूटकर भाग रहा विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया था।

डीएम ने एडीएम भू अध्यापि को बदमाश प्रेम कुमार और अतुल दुबे के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच सौंपी थी। एडीएम ने अपनी जांच में कहा है कि बदमाश अतुल दुबे , प्रेम कुमार काशीराम नवादा गांव के बाहर बने मंदिर के पास छुपे हुए थे सर्च ऑपरेशन के दौरान जब वहां पुलिस पहुंची तो दोनों बदमाशों ने फायर झोंक दिया। मुठभेड़ हुई और दोनों बदमाश मारे गए।

इस मामले में आईजी मोहित अग्रवाल, तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी बाल-बाल बच गए थे। मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को सही माना है। पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दी है। इसी तरह विकास दुबे और प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर की जांच न्यायिक टीम ने की थी। जांच रिपोर्ट में एनकाउंटर को सही मानते हुए पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। डीएम आलोक तिवारी का कहना है कि जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है पुलिस को इसमें क्लीन चिट मिली है।

योगी सरकार का सख्त निर्देश- अधिकारी और कर्मचारी समय से पहुंचें कार्यालय वरना होगी कार्रवाई

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शासकीय कार्यों के जल्द से जल्द पूरा करने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शासन की सख्ती के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपने काम करने का ढंग नहीं बदल रहे हैं। इसका कारण जनता को काफी काठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी तय कर दी है और अनुपस्थित मिलने पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

यूपी के सरकारी कार्यालयों का ढर्रा सुधारने को लगातार प्रयास हो रहे हैं। पत्रावलियों के निस्तारण की समय सीमा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। अब मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किया है कि अधिकारी-कर्मचारियों की हाजिरी का औचक निरीक्षण किया जाए। जहां ज्यादा कार्मिक अनुपस्थित मिलते हैं, वहां पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं।

राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के कार्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक बार समय से उपस्थिति का औचक निरीक्षण जरूर करें। इस दौरान अनुपस्थित मिलने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इसके अलावा जिन कार्यालयों में अधिक संख्या में अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिलें तो वहां पर्यवेक्षणीय अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि इसी प्रकार शासन स्तर पर समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को भी अपने विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिहार की राजनीति में खरमास बाद नहीं आया भूकंप, टांय-टांय फिस्स रहे दलों में टूट के दावे

पटना । नेताओं के दावे पर भरोसा करना फिर भारी पड़ रहा है। बीते साल के 14 दिसम्बर से नए साल के 14 जनवरी तक नेताओं ने जितने दावे किए, सब अमल में आ जाते तो राज्य का राजनीतिक माहौल बदल गया रहता। यूं कहिए कि राजनीतिक दलों में भूकंप का सीन रहता। सबकुछ उलटा-पुलटा और तहस-नहस। क्योंकि इस दौर में हरेक दल में भारी टूट का दावा किया गया। यहां तक कि नई सरकार के गठन तक की कल्पना कर ली गई। दावे इतने जोर से किए जा रहे थे कि जनता उसे सच मान बैठी। लेकिन, खरमास गुजरे सप्ताह होने को आए, किसी दल में टूट की सुगबुगाहट नहीं है। हां, नेताओं के दावे पर एक बार फिर भरोसा टूटा है।

पहले से ही दलों में टूट के दावे

दलों में टूट के दावे पहले से किए जा रहे थे। उसमें गंभीरता 10 जनवरी को आई, जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट का दावा किया। उन्होंने कहा- आरजेडी के नेता तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। हम चुप हैं। अभी खरमास चल रहा है। संक्रांति के बाद आरजेडी अपनी पार्टी बचा ले।

कोई और दावा करता तो लोग टाल देते। मगर यहां मामला भूपेंद्र यादव जैसे बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार का था, सो लोगों ने भरोसा कर लिया। अगले दिन सोमवार को लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह के दावे ने लोगों को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि सचमुच मकर संक्रांति के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ललन सिंह ने कहा- भूपेंद्र यादव चाह लें तो आरजेडी का बीजेपी में मर्जर हो जाएगा।

कांग्रेस में टूट की भविष्यवाणी

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह ने ठंडे के मौसम में राजनीति के माहौल को गर्म कर दिया कि कांग्रेस विधायक दल में बड़ी टूट होने वाली है। पार्टी के 19 में से 11 विधायक जेडीयू में जाने के लिए तैयार हैं। देरी संख्या के चलते हो रही है। विधायक दल में टूट के लिए 13 विधायकों का एकसाथ आना जरूरी है। सिंह के दावे को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने खारिज कर दिया। फिलहाल यह मामला ठंडा हो गया है।

जेडीयू को तोड़ रहा था आरजेडी

सभी दल मिलकर आरजेडी को तोड़ रहे थे तो वह भला कैसे पीछे रहता। उसके नेता श्याम रजक ने दावा कर दिया कि खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी। जेडीयू के 43 में से 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। बस, 13 विधायक और टूट जाएं तो सरकार गिर जाएगी। रजक के दावे के बाद जेडीयू के कुछ विधायकों की ओर शक की सूई घूमने लगी।

क्योंकि जेडीयू में अगर टूट होती है तो न सिर्फ राष?ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चली जाएगी, बल्कि तेजस्वी यादव बड़ी आसानी से सरकार बना लेंगे। सरकार बनाने के लिए उन्हें महज 13 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी के 75 के अलावा कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं। यह संख्या 110 है। 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए।

खरमास के साथ दावा भी खत्म

14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ खरमास खत्म हो गया। अब कोई भी दल टूट का दावा नहीं कर रहा है। नई चर्चा कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही है। यह हो जाए तो नए सिरे से टूट फूट की चर्चा होगी। तब कहा जाएगा कि कैबिनेट में जिन विधायकों को जगह नहीं मिली है, वे दूसरे दल में जाएंगे। गिनती के विधायकों के बल पर चलने वाली सरकार में इस तरह के कयास चलते रहते हैं। बिहार इस मामले में भी अपवाद रहा है। 1990 में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी अल्पमत की सरकार चुनाव दर चुनाव 15 साल चली।

ढाई दशक बाद भी नहीं बन सका स्टेडियम, इस तरह खेल का अभ्यास कर रहे खिलाड़ी

सुपौल। त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में खेल प्रतिभा की कमी नही है। हर क्षेत्र में खिलाड़ियों की लंबी कतार है। लेकिन अभ्यास के लिए स्टेडियम जैसी व्यवस्था नहीं है। अनुमंडल बनने के ढाई दशक बाद भी त्रिवेणीगंज में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में अनुमंडल में खेल गतिविधियां शून्य पड़ गई है और खिलाड़ियों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम के नाम पर एएलवाई कॉलेज समेत कई हाईस्कूल का मैदान उपलब्ध है। खिलाड़ी अभ्यास करने के लिए एएलवाई कॉलेज, साइंस कॉलेज, जेनरल हाईस्कूल मैदान या आरकेबीए हाईस्कूल मैदान पर जाते हैं। स्टेडियम के अभाव में खेल प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं।

क्या कहते हैं खेलप्रेमी- रवि कुमार कहते हैं त्रिवेणीगंज में खेल स्टेडियम नहीं रहने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ी सही तरीके से खेल का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। उनकी खेल के प्रति रुचि कम हो रही है। यह खेल के लिए अच्छा नहीं है। निरंजन वर्मा कहते हैं कि स्टेडियम नहीं रहने से बेहतर खेल प्रतियोगिता कराने में भी खिलाड़ी सफल नहीं हो पाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को खिलाड़ियों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। तरुण ड्क्षसह राठौर बताते हैं कि प्रखंड के युवाओं में खेल से काफी लगाव है। यहां खेल प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन यहां एक भी स्टेडियम नहीं है। राज्य सरकार ने प्रखंड स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे लाभ नहीं हुआ।

लंबे समय से स्टेडियम बनाने की हो रही मांग- त्रवेणीगंज में लंबे समय से स्टेडियम बनाने की मांग की जा रही है। दरअसल, यहां के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर दमखम दिखा चुके हैं। इसके बाद भी यहां पर अब तक खेल के विकास के लिए सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका है। लोगों ने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों ने इस मुद्दे के कई बार उठाया है।

पीसीएस 2018 की कटऑफ मार्क्स लिस्ट जारी, अभ्यर्थी असंतुष्ट

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक (पदवार व श्रेणीवार कटऑफ मार्क्स) जारी किया है।

संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी ने बदले पैटर्न पर यह परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम सितंबर में जारी किया था। लेकिन, अभ्यर्थियों का पदवार व श्रेणीवार कटऑफ अंक जानने की उत्सुकता थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में स्केलिंग नहीं की। पद अधिक होने के बावजूद मेरिट में ज्यादा अंतर नहीं है। अभ्यर्थियों का ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर 25 जनवरी तक रहेगा।

यूपीपीएससी ने पीसीएस-2018 का अंतिम परिणाम 11 सितंबर 2020 को जारी किया था। इसमें 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल हुए थे।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि पीसीएस-2016 तक स्केल्ड व नानस्केल्ड नंबर जारी किया जाता था। पीसीएस-2017 में सिर्फ स्केल्ड नंबर जारी किया गया। इस बार दोनों में कोई जारी नहीं हुआ। क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व दिव्यांगों का अलग से ब्योरा जारी नहीं हुआ। इससे पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।

बता दें कि पीसीएस-2017 में सामान्य वर्ग का कटआफ अंक 877.27 व ओबीसी का 855.36 था। वहीं पीसीएस-2016 में सामान्य का कटआफ 897.04 व ओबीसी का 893.04 था। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्केलिंग न होने से हिंदी माध्यम छात्रों को नुकसान हुआ है। वहीं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वालों को फायदा पहुंचाया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि स्केलिंग व क्षैतिज आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई है। इसे हाई कोर्ट ने भी माना है। अभ्यर्थियों की याचिका कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है।

प्रमुख पदों का कटऑफ

डिप्टी कलेक्टर : सामान्य वर्ग अधिकतम 1014 व न्यूनतम 954, अनुसूचित जाति अधिकतम 952 व न्यूनतम 892, अनुसूचित जनजाति अधिकतम 834 व न्यूनतम 827, ओबीसी अधिकतम 971 व न्यूनतम 924

पुलिस उपाधीक्षक : सामान्य वर्ग अधिकतम 955 व न्यूनतम 927, अनुसूचित जाति अधिकतम 884 व न्यूनतम 867, अनुसूचित जनजाति अधिकतम 819 व न्यूनतम 818, ओबीसी अधिकतम 921 व न्यूनतम 903

असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर : सामान्य वर्ग अधिकतम 945 व न्यूनतम 921, अनुसूचित जाति अधिकतम 891 व न्यूनतम 869, ओबीसी अधिकतम 919 व न्यूनतम 913

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी : सामान्य वर्ग अधिकतम 953 व न्यूनतम 950, अनुसूचित जाति अधिकतम 891 व न्यूनतम 889, ओबीसी अधिकतम 921 व न्यूनतम 921

खंड विकास अधिकारी : सामान्य वर्ग अधिकतम 923 व न्यूनतम 917, अनुसूचित जाति अधिकतम 868 व न्यूनतम 860, ओबीसी अधिकतम 913 व न्यूनतम 907

पश्चिम चंपारण के अजय कुमार इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ गांव के बच्चों को दे रहे निशुल्क शिक्षा

पश्चिम चंपारण । बच्चों को शिक्षित करने और शिक्षित समाज की स्थापना के जुनून में जिले के चनपटिया प्रखंड के लोहियरिया महुअवा गांव निवासी किसान महेंन्र प्रसाद के पुत्र इंजीनियर अजय कुमार ने इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और अब अपने गांव के बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। गांव के बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनें, इसके लिए निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म और पले बढ़े अजय आरंभ से हीं गरीबों की सेवा में तत्पर रहे। अपने अध्ययनकाल में गरीब सहपाठियों की मदद भी की। पंद्रह वर्ष तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर अभियंता काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अभी गांव में आकर बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं।

इंजीनियर अजय ने उनके पिता का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने। सो, उन्होंने 2005 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और मैरीन कंपनी में टेक्निकल सुपरटेंड के पद पर योगदान दिया। पंद्रह वर्ष तक नौकरी की। महनागरीय परिवेश में रहा। लेकिन गांव की याद आती थी। गांव के बच्चों को मदद करने की चिंता रहती थी। जब भी कभी पर्व -त्योहार के मौके पर गांव आते थे तो गांव के बच्चों को हरसंभव मदद भी करते थे। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में घर लौटे। घर से हीं कंपनी का काम भी कर रहे थे। स्कूल - कॉलेज बंद होने के कारण गांव के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा था।

अजय ने पहले अपने गांव के पांच बच्चों को शिक्षा देना आरंभ किया। अभी रानीपुर, रमपुरवा, कुमारबाग, लालगंज, अवरैया आदि गांव के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। तीन बैच में करीब 60 बच्चे मैट्रिक एवं इंटर के साथ मेडिकल और इंजीनियरिग की तैयारी कर रहे हैं। मैट्रिक का छात्र मनीष कुमार ने बताया कि कोविड की वजह लॉकडाउन के कारण स्कूल और कोचिंग बंद हो गए थे। उस वक्त इन्होंने पढ़ाई आरंभ की।

अभी कोर्स पूरी तरह से कंपलिट हो चुका है। 11 वीं की छात्रा साधान, 12 वीं के छात्र पंकज , आलोक , मनोरंजन आदि ने बताया कि कोविड महामारी के काल में ये हमसभी के लिए वरदान बनकर आए। जिस तरह से स्कूल और कोचिंग बंद थे, कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा था। वैसे में इन्होंने गांव में शारीरिक दूरी का पालन कर प्रोपर सुरक्षा के साथ बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। पढ़ाई के लिए कोई फीस भी नहीं लेते हैं।

बिहार : सीएम नीतीश के कैबिनेट में शाहनवाज हुसैन की एंट्री तय

पटना । बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपने कोटे के संभावित नामों की सूची को अंतिम रूप देना है। चर्चा है कि बीजेपी ने भी अपने संभावित मंत्रियों के नाम तय तो कर लिए हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की अंतिम मुहर का पार्टी को इंतजार है। इसके लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता सुशील मोदी, नित्यानंद राय और राधामोहन सिंह जैसे नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई नामों की चर्चा है। इनमें शामिल बीजेपी के शाहनवाज हुसैन की एंट्री तय मानी जा रही है।

बीजेपी का फोकस सामाजिक-क्षेत्रीय समीकरण पर- बीजेपी सूत्रों की मानें तो विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित पार्टी का सारा फोकस इस बार सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर है। यही वजह है कि संभावित मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप देने में समय लग रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस जाति के विधायकों की संख्या अधिक होगी, उसको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं।

अभी कैबिनेट में हैं मुख्यमंत्री को लेकर 14 मंत्री- फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री हैं। बीजेपी के कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री हैं। इन दो के अलावा मंगल पांडेय, अमरेंद्र प्रताप सिंह , जीवेश मिश्रा , रामसूरत राय , रामप्रीत पासवान मंत्री हैं। यानी 13 में से सात मंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी सरकार में मंत्री हैं। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कोटे से अब तक विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी और शीला मंडल को मंत्री बनाया है। इन चार के अलावा जेडीयू की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन भी मंत्री हैं।

22 नए चेहरों को मिल सकती है नीतीश कैबिनेट में जगह

नियमों के मुताबिक प्रदेश कैबिनेट में एक मुख्यमंत्री के अलावा 35 मंत्रियों का कोटा है। इस लिहाज से 22 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि, अब तक यह तय नहीं हुआ है कि नए मंत्रियों में कितने बीजेपी कोटे के होंगे और कितने जेडीयू के। सूत्रों की माने तो नए मंत्रिमंडल में 11-11 या फिर 10-12 के फॉर्मूले पर नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

शाहनवाज व संजीव चौरसिया के नाम सूची में शामिल- बीजेपी की ओर से जिन नए चेहरों में मंत्रिमंडल में शामिल करने के लेकर माथापच्ची चल रही है उनमें वैश्य समाज से आने वाले संजय सरावगी, पिछड़ी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी, महादलित बिरादरी से आने वाली भागीरथी देवी, कृष्ण कुमार ऋषि, केंद्र की राजनीति करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया, पहली बार लालगंज से चुनाव जीतने वाले संजय सिंह, रामप्रवेश राय, राणा रणधीर के अलावा दीघा विधान सभा सीट से जीतने वाले संजीव चौरसिया का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है।

श्रवण, लेसी, महेश्वर और कृष्णनंदन भी बन सकते हैं मंत्री

दूसरी ओर जेडीयू ने अपने कोटे से जिन लोगों को मंत्री पद सौंपने की तैयारी की है उन चेहरों में श्रवण कुमार, लेसी सिंह, सुधांशु शेखर, सुमित सिंह, शालिनी मिश्रा, नीरज कुमार, महेश्वर हजारी, मदन सहानी, बीमा भारती के अलावा कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का नाम प्रमुख से लिया जा रहा है। संभावना है कि दो-चार रोज के अंदर दोनों दलों के प्रमुख आपस में बैठकर नामों सहमति बनाएंगे और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का आधिकारिक एलान कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जीएडी की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

पात्र शासकीय सेवकों को शीघ्र दी जाए पदोन्नति

सिर्फ निर्देश जारी करना काफी नहीं, बताएं क्या कार्य हुआ

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों के शासकीय कर्मचारियों को पात्रता अनुसार शीघ्र पदोन्नति दी जाए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) बिना विलंब के नियमानुसार सर्वसम्मत हल निकालकर कार्रवाई करे। अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।

श्री चौहान बुधवार को यहां मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, प्रमुख सचिव मनोज गोविल, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारी यह न लिखे कि निर्देश जारी किए गए, यह बताएं कि क्या कार्य हुआ है। केवल कनिष्ठ कार्यालय को निर्देश जारी करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व नहीं है। कार्य सुनिश्चित कराना भी जरूरी है।

सेवानिवृत्ति पर हो स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान

सीएम ने निर्देश दिए कि सभी शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके सभी स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह कर्मचारी कल्याण का प्रमुख बिन्दु हैं।

प्रदेश में लागू हो ई-ऑफिस प्रणाली

श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ की जाए। सर्वप्रथम मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए। इसके लिए टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाएं तथा आवश्यक प्रशिक्षण दें। मंत्रियों, विधायकों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए। शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए।

समय पर मिलें जाति, आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र

उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदकों को जाति, आय, मूल निवास आदि प्रमाण-पत्र समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग सुपरविजन कर इस कार्य को सुनिश्चित कराए। उन्होंने निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। यह अन्य विभागों के कार्य का सुपरविजन भी करता है। इसका कार्य 'परफेक्ट' होना चाहिए।

प्रदेश के बाहर प्रदेश की संपत्ति पर न हो कब्जे

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश की अन्य प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की नियमित रूप से देखरेख की जाए तथा उन पर कब्जे न हों, इसका ध्यान रखा जाए। बताया गया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप की अनुशंसा के अनुरूप मध्यप्रदेश लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हर शासकीय कर्मचारी को सूचना तकनीकी में दक्ष होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।

मंत्री राजपूत ने मुख्यमंत्री से किया ग्वालियर मेले में पंजीयन शुल्क की छूट देने का आग्रह

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंत्रियों से चाय पर मुलाकात का सिलसिला जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री से मंत्रालय में परिवहन एवं राजस्व मंत्रीगोविंद सिंह राजपूत ने चर्चा की। मंत्री श्री राजपूत ने सीएम से ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के बिक्री में पंजीयन शुल्क की छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ग्वालियर मेला सौ साल पुराना है। इस मेले में देशभर के लोग शामिल होने आते हैं। मेले में बड़ी तादाद में वाहनों की बिक्री भी होती है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि ग्वालियर मेले के सचिव एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर मेले में छूट देने के लिए पत्र लिखा है। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध इस मेले में छूट मिलने से वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि की संभावना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर मेले में वाहनों की बिक्री पर छूट दिए जाने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ चाय पर मुलाकात की जो पहल शुरू की है, उसके काफी सार्थक परिणाम मिल रहे हैं।

प्रदेश में लैंड टाइटलिंग के लिए बनेगा कानून

मुख्यमंत्री ने की राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मौका, नक्शा एवं खसरा में समानता होगी तथा विवाद रहित भूमि का भू-स्वामित्व संबंधित भू-स्वामी को प्रदान किया जा सकेगा।

नागरिकों को मिल रही हैं राजस्व संबंधी ऑनलाइन सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर राजस्व सुधार किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उनके मोबाइल पर घर बैठे मिल रही हैं। नागरिकों को भू-अभिलेखों की कहीं से भी प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई हैं। नागरिकों को एम.पी. भू-लेख पोर्टल के माध्यम से भूमि संबंधी सेवाएं, आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से राजस्व न्यायालयों से संबंधित सेवाएं, सारा पोर्टल के माध्यम से गिरदावरी व अन्य सर्वे संबंधी सुविधाएं तथा किसान एप्प के माध्यम से ई-उपार्जन पंजीयन, फसल स्व-घोषणा, गिरदावरी की जानकारी आदि सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान बुधवार को मंत्रालय में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मनोज गोविल आदि उपस्थित थे।

तीन वर्षों में करें कार्य पूर्ण: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि भूमि के नक्शों के डिजिटलाइजेशन का कार्य तीन वर्षों में पूरा किया जाए। कोर्स नैटवर्क की स्थापना कर सीमांकन की सुविधा प्रदान की जाए।

स्वामित्व योजना का त्वरित क्रियान्वयन करें: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में स्वामित्व योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत 22 हजार 580 गांवों का आबादी सर्वे किया जाना है तथा गांवों में मकान, जमीन का स्वामित्व प्रदान किया जाना है। इससे मकान, जमीन पर स्वामित्व हक प्राप्त होने से बैंकों से ऋण लेने सहित कई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

20 लाख किसानों को किसान कल्याण की राशि शीघ्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए के मान से कुल 400 करो? रूपए की राशि शीघ्र ही उनके खातों में अंतरित की जाएगी।

भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रतिलिपि

प्रदेश में भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रति प्रदाय करने की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं से भी नामांतरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। आसामीवार खतौनी प्रदान की भी योजना है। ऑनलाइन भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) तथा ऑनलाइन भूमि बंधक की सुविधा भी दी जा रही है। रैवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नागरिकों को सभी राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज कराने एवं निराकरण की सुविधा दी जा रही है। सारा एप्प के माध्यम से नागरिकों को आबादी सर्वे (स्वामित्व), ई-गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोप पंजी, किसान कल्याण योजना आदि सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

2 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की ई-गिरदावरी सफल

प्रदेश में ई-गिरदावरी के अंतर्गत कुल 2 करो? 62 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 2 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की ई-गिरदावरी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 80.74 प्रतिशत है।

शराब नीति के मामले में जनता के हित में फैसला करेंगे

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने अपनी घोषणा के मुताबिक राज्य में 10 वर्षों तक शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली, अलबत्ता कई दुकानें बंद कर दी गयीं।

श्री चौहान ने शराब मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ट्वीट के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी सरकार ने वर्तमान में माफियाओं को दफन करने का अभियान चलाया हुआ है और यह चलता रहेगा। नयी शराब दुकानों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने 'कौआ कान ले गया' वाली कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि श्री कमलनाथ को तो यह भी पता नहीं है कि'कौआ'है या'कान'। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कुछ भी बोलते हैं। मैंने अपनी घोषणा के अनुरूप राज्य में 10 सालों तक शराब की नई दुकान नहीं खुलने दीं और कई बंद कर दी गयीं। वे अभी इस विषय पर और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। कई तरह के तथ्य आते हैं। उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे।

कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया

क्या कहा था कमलनाथ ने : कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि जो भाजपा चुनाव के पहले शराबबंदी की बात करती थी, वो आज मप्र को शराब के दलदल में झोंकने की तैयारी कर रही है। अब 'जहरीली शराब' के नाम पर शराब दुकानों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी भले ही धार्मिक स्थल और अन्य स्थान बंद रहे, लेकिन शराब दुकानें खुली रहीं। श्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें बढ़ायी गयीं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया जाएगा। श्री कमलनाथ ने एक अन्य ट्वीट के जरिए कहा कि श्री चौहान को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में शराब की नई दुकानें खुलेंगी या नहीं। गोलमोल बात करने से कुछ नहीं होगा।

किसानों के बैंक खाते में आएगा अब बिजली सब्सिडी का पैसा

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा पॉवर सेक्टर (बिजली क्षेत्र) में सुधारों के लिए बनाए गए मानदंडों को लागू करने में मध्यप्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके तहत राज्य ने दिसंबर 2020 से विदिशा जिले में किसानों को बिजली के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते (डीबीटी के जरिए) में देनी शुरू कर दी है। इस प्रकार मध्यप्रदेश ने पॉवर सेक्टर के लिए निर्धारित तीन सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।

मध्यप्रदेश पॉवर सेक्टर रिफॉर्म में निभा रहा है अग्रणी भूमिका

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि बिजली सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने से मध्यप्रदेश को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने की पात्रता मिल गई है। इसके तहत व्यय विभाग ने राज्य को खुले बाजार से 1423 करोड़ रुपए कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। यह राशि राज्य को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद देगी। वित्त मंत्रालय की पॉवर सेक्टर में सुधारों के जरिए कोशिश है कि किसानों को बिना किसी अड़चन के न केवल बिजली सब्सिडी की राशि मिल सके बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोका जा सके। इसके अलावा इन कदमों के जरिए यह भी कोशिश है कि विद्युत वितरण कंपनियों की बैलेंसशीट को भी सुधारा जा सके। इससे उनकी नकदी की समस्या भी धीरे-धीरे खत्म हो सकेगी।

60 हजार 81 किसानों के खाते में पहुंचे 32 करोड़: मध्यप्रदेश ने राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डीबीटी योजना तैयार की है। इस योजना को राज्य के विदिशा जिले में लागू किया गया है। यहां पर योजना को दिसंबर, 2020 से लागू कर दिया गया है। योजना में दिसंबर, 2020 तक 60,081 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ सात लाख रुपए डीबीटी के जरिए भेजे गए। इसके अलावा राज्य ने झाबुआ और सिवनी जिलों में भी डीबीटी योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में तीन जिलों में योजना के लागू होने के बाद, उससे मिले अनुभव के आधार पर योजना को वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

कृषि कानूनों से किसान ही नहीं, इससे जुड़ा हर क्षेत्र होगा बर्बाद : कमलनाथ

मुरैना में विशाल किसान महापंचायत आयोजित

भोपाल (एजेंसी)। हमारे देश की 70 फीसदी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इन तीन किसान विरोधी कानूनों से ना सिर्फ कृषि क्षेत्र व किसान बर्बाद होगा बल्कि इससे जुड़ा हर क्षेत्र बर्बाद होगा। केंद्र सरकार को किसानों की मांग मानते हुए इन किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार तत्काल इन काले कानूनों को वापस लें। कांग्रेस किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ है। जब तक किसानों की मांगें मान नहीं ली जाती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को मुरैना में आयोजित विशाल किसान खाट महापंचायत को सबोधित करते हुए कही।

श्री नाथ ने किसानों को इन तीनों क़ानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किस प्रकार इन कानूनों से कृषि क्षेत्र का निजीकरण होगा, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र और किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कमलनाथ ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि आप सभी से निवेदन है कि आप भले कांग्रेस का साथ मत देनाख लेकिन सच्चाई का साथ ज़रूर देना। सच्चाई ही आपका भविष्य सुरक्षित रख सकती है। हम इस किसान महापंचायत के माध्यम से सच्चाई की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। देश का भविष्य युवा और किसान ही सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन भाजपा इन वर्गों की सबसे बड़ी विरोधी है। सभी ने एक स्वर से इन किसान विरोधी काले क़ानूनों को वापस लेने की मांग की। जब तक इन काले क़ानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, सज्जन वर्मा, गोविंद सिंह, केपी सिंह, दिनेश गुर्जर और राकेश मवई सहित अन्य वरिष्ठजन व हज़ारों किसान उपस्थित थे।

कमलनाथ जहरीली शराब के सेवन से मृत परिवार से मिले और ढांढस बंधाया

मुरैना, (एजेंसी)। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार दोपहर मुरैना जिले के मानपुर गांव में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से एक दर्जन मृत लोगों के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया तथा मृतकों को श्रद्धांजली अर्पित की।श्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को पार्टी की ओर से हरसंभव सहयोग करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान अवैध शराब कारोबार को संरक्षित कर आम आदमी के जीवन से खिलवाड़ करने वाले असल गुनाहगारों को पहचान कर उन्हें दंडित कराने की बात भी कही। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्रीगण सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह यादव, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, जीतू पटवारी, सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा, सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों को मुरैना जिले के कांग्रेस के विधायकों की ओर से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है।

मुरैना जिले के कांग्रेस विधायक देंगे 50-50 हजार की सहायता

राज्य ओपन गरीब युवाओं को घर-घर देगा स्थाई तौर पर रोजगार

भारत सरकार से हुआ अनुबंध, शिक्षा मंत्री ने कहा आत्मनिर्भर की दिशा में नया कदम

भोपाल (एजेंसी)। अपनी बदनाम छवि को निकालते हुए राज्य ओपन मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक काम करने जा रहा है। प्रतिवर्ष पढ़ाई में कमजोर ज्यादातर गरीब विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाने वाला राज्य ओपन अब युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए भारत सरकार से अनुबंध किया गया है।

इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पूरे प्रदेश के जिलों में व्यावसायिक आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण

दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के हैंडीक्राफ्ट एंड कार्पेट सेक्टर स्किल काउंसिल और मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, मेटैलवेयर, बुनकर, नक्काशी आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री परमार ने कहा कि इसमें विद्यालयीन छात्रों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर युवाओं को भी लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का यह एक महत्वपूर्ण साधन होगा। नई शिक्षा नीति में कक्षा 6वीं से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इस नीति के पालन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले से स्थानीय स्तर पर ही ट्रेनर का चयन कर उसे प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ट्रेनर छात्रों और युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हैंडीक्राफ्ट एंड कार्पेट सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा दिया जाएगा जिसकी वैश्विक स्तर पर मान्यता रहेगी। एमओयू साइन करने के दौरान निदेशक राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रभात राज तिवारी और काउंसिल के सीईओ श्री कृष्ण कुमार उपस्थित थे।

शिवराज ने प्रकाश पर्व पर किया गुरु गोविंद सिंह का स्मरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिखों के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया है। श्री चौहान ने ट्वीट के जरिए श्री गोविंद सिंह के वचनों का भी स्मरण करते हुए लिखा है'अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे, तो वर्तमान भी खो देंगे। श्री चौहान ने कहा कि धर्म और मानवता के सच्चे सेवक, सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर कोटिशः नमन। दीन-हीन और असमर्थों की सेवा और कल्याण ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सिखों के दसवें गुरु, खालसा पंथ के सृजनहार गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सभी को लख-लख बधाई प्रेषित की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म व समाज की रक्षा की ख़ातिर अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। उनका एकता, भाईचारे व मानवता का संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य नेताओं ने भी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) पर उनका स्मरण करते सभी को बधाई दी हैं।

किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारा पहुंच कर मत्था टेका

देश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा हंडिया

चार सौ साल पहले हंडिया आए थे गुरु गोविंद सिंह, व्यास परिवार ने सहेज कर रखी है हस्तलिखित सनद

भोपाल (एजेंसी)। हरदा जिले का हंडिया देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के मानचित्र पर उभरेगा। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हंडिया के गुरुद्वारे में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। करीब 400 वर्ष पूर्व गुरु गोविंद सिंह हंडिया आए थे, यहां गोकुल प्रसाद व्यास के परिवार ने उनकी सेवा की थी।

गुरु गोविंद सिंह ने यहां अपने हाथ से लिखकर सनद दी थी जिसे व्यास परिवार सहेज कर रखे हुए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि यहां गुरु गोविंद सिंह पधारे थे। उन्होंने कहा कि एक ओर रिद्धनाथ तो दूसरी ओर सिद्ध नाथ के साथ मां नर्मदा के इस नाभि स्थल पर भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कर गुरु गोविंद सिंह की स्मृति को सहेजा जाएगा। मंत्री पटेल ने कहा कि हंडिया धार्मिक महत्व का स्थान है, यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास तेज किया जाएगा। मंत्री पटेल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर हरदा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कोमल सूदीप पटेल डूडी भी साथ थीं।

प्रदेश के युवा स्व-रोजगार से बनें स्वावलंबी : पटेल

भोपाल। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे युवा स्व-रोजगार कर स्वाबलंबी बन रहे हैं। श्री पटेल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर हरदा में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। रोजगार मेले में 352 युवाओं का पंजीयन किया गया, जिसमें से 205 युवाओं का चयन किया गया। मंत्री श्री पटेल ने मेले में 165 हितग्राहियों को एक करोड़ 49 लाख 82 हजार रुपए की राशि के लाभ-पत्र वितरित किए। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कृषि उपज मंडी हरदा में 12 लोगों को रोजगार के स्वीकृति-पत्र भी दिए। रोजगार मेले में रिम्स ग्रुप नागपुर द्वारा 35 आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिए गए। रोजगार मेले में 352 युवाओं का पंजीयन हुआ। मेले में 12 कंपनियों ने सहभागिता की।

युवा पराक्रम दिवस के आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि संघर्ष और बलिदान की अमिट गाथा लिखने वाले अमर शहीद नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 124वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। यह देश के युवाओं को सदैव संघर्ष कर देशहित में आगे बढ़कर निः संकोच बलिदान देने में प्रेरित करेगा। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए युवाओं से आयोजनों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने का आह्वान किया।

इस वजह से 2 बार शादी करना चाहती हैं जन्नत गर्ल सोनल चौहान

फिल्म 'जन्नत' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सोनल चौहान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती है। अब सोनल ने अपनी शादी को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद वह चर्चा में आ गई हैं। सोनल चौहान ने कहा कि वह दो शादियां करना चाहती हैं। एक समंदर किनारे और दूसरी पहाड़ों पर। उन्होंने यह बात प्रकृति के बारे में चर्चा करते हुए बोली है। खबर के अनुसार सोनल चौहान ने कहा है कि वह प्रकृति से बहुत प्यार करती हैं। इसलिए वह दो शादियां करना चाहती हैं। अभिनेत्री ने कहा, 'हां, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, यह काफी सुखद है। हमारी जिंदगी में इसका बहुत महत्व है। प्रकृति की तुलना में मुझे और किसी से खुशी नहीं मिलती है। चाहे वह बाहर की सैर कर रहा हो या पेड़ों के करीब जाना है। या फिर बस सुबह-सुबह पक्षियों के चहकने की आवाज सुनना हो। यही वजह है जोकि मुझे जल्दी जागना पसंद है।' इसके बाद सोनल चौहान ने अपनी शादी को लेकर भी बात की। वह चाहती है कि उनकी शादी प्रकृति के साथ पृष्ठभूमि के रूप में हो। सोनल चौहान ने कहा, 'जब मैं शादी करूं तो मैं दो शादियां करना चाहती हूं। एक समंदर के किनारे और एक पहाड़ों पर। एक रेत में और एक सुंदर चट्टान पर तो वह बहुत प्यारी होगी।' वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनल चौहान ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म जन्नत से की थी। उनकी यह फिल्म साल 2008 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद सोनल चौहान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। हालांकि सोनल चौहान बॉलीवुड में अपना ज्यादा नाम नहीं कमा सकीं। इसे बाद उन्होंने साउथ फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। सोनल चौहान ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की कई फिल्मों में काम किया है। वह आखिरी बार तेलुगु फिल्म रूलर में नजर आई थीं। सोनल चौहान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप साबित हुई।

सलमान खान बने रियलिटी म्यूजिक लीग के ब्रांड एंबेसडर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के ब्रांड एंबेसडर के रूप में चुना गया है। सलमान ने कहा, ''हम सभी को खेल के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना के लिए खेल लीग के लिए प्रेरित किया गया है, लेकिन पूरी टीम एक म्यूजिक लीग के साथ आई, जो संगीत की वास्तविकता टेलीविजन की दुनिया में खेल की ऊर्जा को प्रभावित करती है।'' उन्होंने कहा, ''यह पहली बार है कि बड़ी फिल्म और स्पोर्ट्स सेलेब्स बॉलीवुड के 12 शीर्ष पाश्र्व गायकों, रियलिटी सितारों और 6 ताजा आवाजों की अगुवाई वाली टीमों का समर्थन कर रहे हैं, जो एक संगीत चैंपियनशिप की लड़ाई में भाग लेंगे, जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।'' संगीत लीग में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें होंगी। इन छह टीमों में से प्रत्येक प्रमुख बॉलीवुड और खेल हस्तियों द्वारा समर्थित है, और कप्तान के रूप में शीर्ष पाश्र्व गायक होंगे। शो से जुड़े अन्य बॉलीवुड सितारे हैं, जैसे श्रद्धा कपूर के साथ उनके पिता शक्ति कपूर और भाई सिद्धांत कपूर, राजकुमार राव, गोविंदा और पत्नी सुनीता, रितेश देशमुख के साथ पत्नी जेनेलिया डीसूजा देशमुख रहेंगे। यह शो फरवरी में प्रसारित होगा। यह जी टीवी और जी5 पर प्रसारित होगा।

फिर से टीवी शो की शूटिंग पर लौट कर बहुत अच्छा लग रहा

अभिनेता यश टोंक टीवी शो में एक लंबे ब्रेक के बाद कैमरे का सामना कर रहे हैं। अभिनेता को सेट पर वापस आकर आनंद का अनुभव हो रहा है। यश को आखिरी बार धारावाहिक रूप – मर्द का नया स्वरुप में देखा गया था। अब वह अपने अगली धारावाहिक क्यूं उत्थे दिल छोड़ आए में दिखाई देंगे। नए शो में वह लाला बृज किशोर के किरदार में नजर आएंगे। यश ने कहा, टेलीविजन शो में वापसी करके काफी खुशी हो रही है। प्री-पार्टिशन की दर्दनाक पृष्ठभूमि में सेट धारावाहिक क्यूं उत्थे दिल छोड़ आए 1940 के दशक में असंभव सपने देखने की हिम्मत करने वाली तीन युवतियों की कहानी बयां करती है। उन्होंने कहा, मेरा किरदार लाला बृज किशोर का है, जो बहुत मासूम और गुस्सैल है। अभिनेता को क्यूंकी सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, जस्ट मोहब्बत जैसे शो के लिए जाना जाता है। क्यूं उत्थे दिल छोड़ आए 25 जनवरी को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रीमियर होगा।

महेश मांजरेकर पर लगा मारपीट करने का आरोप

बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर पर एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने और गाली देने का आरोप लगाया है। खबरों के अनुसार ये लड़ाई कार में टक्कर लगने के बाद शुरू हुई जहां उन्होंने हाथापाई की। व्यक्ति ने पुणे के यवत पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना 15 जनवरी की है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। बता दें कि बीते अगस्त महीने में महेश मांजरेकर को फोन पर डारने-धमकाने की कोशिश की गई थी और उनसे 35 करोड़ रुपए मांगे गए। जिसके बाद उन्होंने दादर पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। महेश मांजरेकर बॉलीवुड के बड़े निर्देशकों में से एक हैं। जिन्होंने संजय दत्त समेत कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। वहीं संजय दत्त के साथ उनकी फिल्म 'वास्तव' ने कई बड़े पुरस्कार अपने नाम किए।

राम मंदिर निर्माण के लिए अक्षय ने दिया सहयोग

अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राम मंदिर निर्माण में सहयोग देने के लिए 'राम मंदिर समर्पण निधि' अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हरकोई अपना सहयोग दे रहा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए आर्थिक रूप से मदद की है। अक्षय ने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की है कि वो इस नेक काम में अपना हाथ बटाएं और मंदिर निर्माण कार्य में सहभागी बनें। अक्षय ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। अक्षय ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, 'जय सियाराम। बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चूका है। अब योगदान की बारी हमारी है। मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी साथ जुड़ेंगे। जय सियाराम।' बता दें कि अक्षय कुमार जल्द ही राम सेतु टाइटल के साथ अपनी एक फिल्म भी लेकर आ रहे हैं जिसे लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुंबई में चर्चा भी की थी।

इंडस्ट्री में आउटसाइडर

इनसाइडर में फर्क किया जाता है

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को इंडस्ट्री में कदम रखे दो साल हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने उतार-चढ़ाव पर बात की। सारा अली खान का कहना है कि इंडस्ट्री में भेदभाव किया जाता है, अगर आप आउटसाइडर होते हैं या इन्साइडर होते हैं। सारा अली खान कहती हैं, मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मैं इंडस्ट्री का हिस्सा रही। पहले इंडस्ट्री का हिस्सा न रहना और फिर इंडस्ट्री में कदम रखना, इन दोनों ही जिंदगियों में बदलाव आता है। आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। चीजें बदलती हैं जब आप आउटसाइडर होते हैं या फिर इन्साइडर होते हैं। मैं भूल चुकी हूं उस समय को जब मैं इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी। सारा आगे कहती हैं कि जो भी निर्णय लेती हूं वह मेरे होते हैं, लेकिन मैं अपनी मां अमृता सिंह की सलाह लेती हूं, इसके बाद डिसाइड करती हूं। मैं जो भी करती हूं, मां की राय के बिना नहीं करती। फिर वह फिल्म साइन करना हो या स्टाइलिंग टिप्स। मैं उनसे पूछती हूं, लेकिन वह हमेशा कहती हैं कि मां की सुनो, मैं तुम्हें बता सकती हूं कि मैं क्या सोचती हूं? लेकिन तुम्हें अपने कन्विक्शन (पूर्ण विश्वास) पर भी भरोसा रखना होगा। अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मत करो। मां कहती हैं कि करियर में यही उनका मंत्र रहा है।

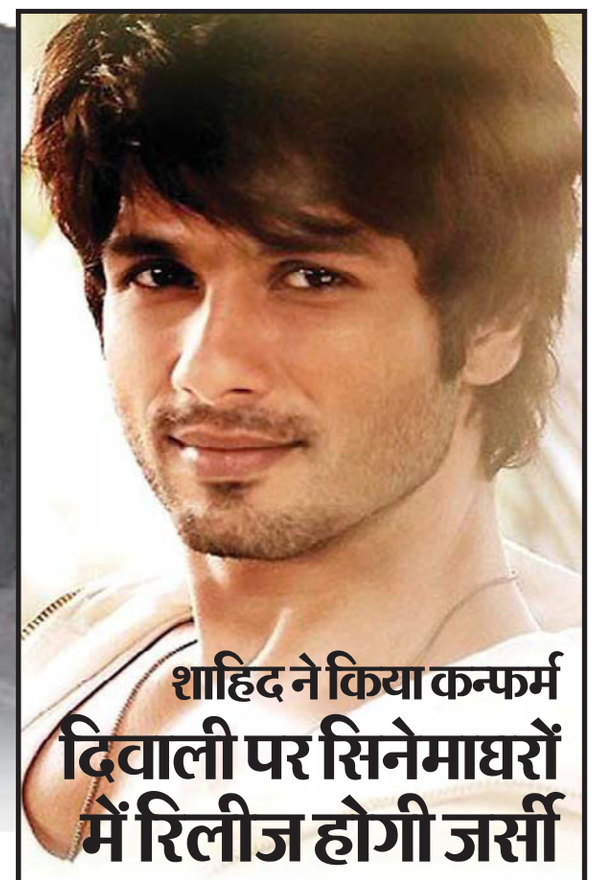

शाहिद ने किया कन्फर्म

दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी जर्सी

'जर्सी' में शाहिद के ऑपोजिट लीड ऐक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हैं। इस फिल्म में पंकज कपूर भी अहम रोल में हैं। शाहिद कपूर ने दिवाली 2021 को लेकर पहले ही चार-चांद लगा दिए हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि आने वाली स्पॉर्ट्स ड्रामा फिल्म 'जर्सी' दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। अपने सोशल मीडिया पर हैंडल शाहिद ने लिखा, 'जर्सी 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ऐसी जर्नी जिस पर मुझे गर्व है। यह टीम के लिए है।'

दिवाली पर सेलिब्रेट करें फिल्म जर्नी

फिल्म के प्रड्यूसर अमन गिल ने एक बयान में कहा, 'दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार है और जर्सी को दर्शकों के सामने पेश करने का यह पर्फेक्ट टाइम है। उस वक्त परिवार के सभी लोग मिलकर इस जर्नी को सेलिब्रेट कर सकते हैं।'

दिसंबर 2020 में पूरी हो गई थी शूटिंग

बता दें, टीम ने दिसंबर 2020 में शूट पूरा कर लिया था। इसकी जानकारी खुद शाहिद ने सोशल मीडिया पर एक लंबे-चौड़े पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने बताया था कि कोविड के दौरान 47 दिनों का शूट चला।

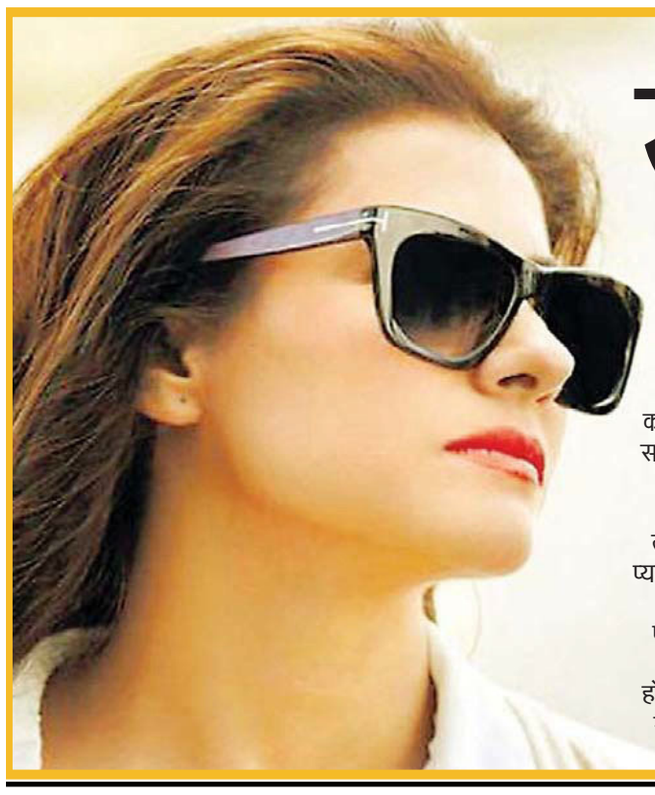

खुद की बेटी होने पर अपनी मां को समझ पाई

बॉलीवुड स्टार काजोल का अपनी मां व वरिष्ठ अभिनेत्री तनुजा से काफी लगाव है। वह कहती हैं कि खुद की बेटी होने के बाद ही उन्होंने सही मायने में अपनी मां को समझा। अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी निसा के होने के बाद अपनी मां के बलिदानों का एहसास हुआ। काजोल ने कहा, ''मैंने अपनी मां को तभी सही तरीके से जाना जब मेरी खुद की बेटी हुई। मैं हमेशा अपनी मां से प्यार करती थी, हमेशा उनकी प्रशंसा करती थी और सोचता थी कि वह शानदार हैं। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मुझे अपनी मां को फोन करना और उनके साथ रोते हुए बातें करना सब याद है और उनसे कहती थी, 'मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो'।'' बातचीत को याद करते हुए काजोल ने कहा, ''उस समय, मैं समझ गई थी कि वह मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैंने उनसे कहा 'आज, मैं समझती हूं कि आपने मेरे लिए कितने त्याग किए, आपने जीवन में हर चीज के बारे में कैसा महसूस किया, क्योंकि मैं थी आपके पास और आपके लिए सब कुछ कैसे बदल गया'।'' अभिनेत्री ने कहा, ''और यह भी कि उन्होंने मेरी मां बनने पर कितना कुछ किया। मुझे यह तभी समझ आया, जब मेरी खुद की बेटी हुई। मुझे अहसास हुआ कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा। यह जानने के बाद मेरी मां के लिए मेरे मन में सम्मान 100 गुना बढ़ गया।'' अभिनेत्री ने आगे कहा, ''मुझे याद है कि जब हम छुट्टियों पर जाने वाले होते थे, तब वह फिल्मों को ना कह देती थीं। वह कहती थी, 'मुझे क्षमा करें, मैं अप्रैल और मई के महीने में काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं और मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनके साथ रहूंगी'।''

पंत करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर, विराट एक स्थान खिसके

दुबई, एजेंसी। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में पहुंच गए हैं जबकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक स्थान फिसलकर चौथे नंबर पर आ गए हैं। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट की दूसरी पारी में 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 89 रन बनाए थे जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला और वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 13वें स्थान पर आ गए। पंत अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में पहुंच गए। पंत ने सीरीज में 274 रन बनाए। इसके साथ ही पंत उच्च रैंकिंग वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला था जिसके बाद वह अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट गए थे। अगले तीन टेस्ट में नहीं खेलने का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और वह तीसरे स्थान से खिसकर चौथे नंबर पर पहुंच गए। तीसरे स्थान पर उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन आ गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया था। न्यूजीलैंड के कप्तान बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ दूसरे नंबर पर हैं। पंत के बाद विकेटकीपर बल्लेबाजों के मामले में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक हैं जो बल्लेबाजी रैंकिंग में 15वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रुट शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा था। रुट टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं जबकि भारत के चेतेश्वर पुजारा एक स्थान के सुधार के साथ सातवें नंबर पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज ब्रिस्बेन में छह विकेट लेने की बदौलत 32वें स्थान से 45वें नंबर पर आ गए हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड न्यूजीलैंड के गेंदबाज टिम साउदी को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे स्थान पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हार हैरान करने वाली : पोंटिंग

मेलबोर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि टीम की ऐसी हार हैरान करने वाली है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास टीम में सभी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे और वह सीरीज में पूरे दम के साथ उतरी थी जबकि टीम इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। टीम इंडिया इस सीरीज में अपने नियमित कप्तान विराट कोहली के बिना खेली थी जो पहले टेस्ट के बाद अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट गए थे। टीम इंडिया 20 सदस्यों के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गयी थी लेकिन एक के बाद एक उसके कई खिलाड़ी चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। इसके अलावा तीसरे और चौथे टेस्ट में मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गयी लेकिन भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से कंगारु टीम को हर मोर्चे पर जवाब दिया। पोंटिंग ने कहा, मैं काफी हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। भारतीय टीम पिछले पांच-छह सप्ताह में कई चुनौतियों से गुजरी है। उनके नियमित कप्तान विराट पहले टेस्ट के बाद स्वदेश लौट गए। इसके बाद टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास सभी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे और बाद में डेविड वार्नर भी टीम से जुड़ गए, इसलिए इस हार को पचा पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, भारत ने काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने मेहनत की और हर दिन मैच में पकड़ बनायी तथा सीरीज के सभी बड़े क्षण को जीता। दोनों टीमों के बीच यह अंतर है। भारत ने टेस्ट मैच के सभी बड़े पलों को जीता लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने में नाकाम रही।

संक्षिप्त खबरें

जेएसडब्ल्यू ने ऋषभ पंत को अनुबंधित किया

मुंबई, एजेंसी। आस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय जीत के नायक रहे स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के साथ कई साल का करार किया है जिसके तहत यह कंपनी इस क्रिकेटर के व्यावसायिक और विपणन अधिकारों को देखेगी। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने बुधवार को पंत के साथ अनुबंध करने की घोषणा की। इससे पहले पंत कार्नरस्टोन स्पोर्ट एंड इंटरटेनमेंट प्रा.लि. से जुड़े थे। पंत की नाबाद 89 रन की पारी की मदद से भारत ने मंगलवार को 328 रन का लक्ष्य हासिल करके आस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट में तीन विकेट से हराया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीतकर बोर्डर-गावस्कर ट्राफी भी बरकरार रखी। जेएसडब्ल्यूए स्पोर्ट्स अधिकतर ओलंपिक खेलों, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़े खिलाड़ियों का काम देखता रहा है। इनमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और एक अन्य स्टार पहलवान बजरंग पूनिया भी शामिल हैं।

वुड्स की पीठ का पांचवां आपरेशन, अगले दो टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे

न्यूयॉर्क,एजेंसी। दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को पीठ दर्द से निजात पाने के लिये हाल में पांचवीं बार आपरेशन करवाना पड़ा जिसके कारण वह अगले दो टूर्नामेंटों में नहीं खेल पाएंगे। टीजीआर फाउंडेशन के मंगलवार को जारी बयान में कहा कि वुड्स का आपरेशन सफल रहा और उनके जल्दी पूरी तरह फिट होने की संभावना है। वुड्स इस वजह से अगले सप्ताह टोरे पाइन्स में फार्मर्स इन्सुरेन्स ओपन में भाग नहीं ले पाएंगे जिसमें वह सात बार चैंपियन रहे। उन्होंने यहां आखिरी खिताब 2013 में जीता था। वह रिवेरा में 18-21 फरवरी के बीच होने वाले जेनिसिस ओपन में भी भाग नहीं ले पाएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का यू टर्न हार के बाद भारत की ऐतिहासिक जीत की तारीफ की

ब्रिस्बेन, एजेंसी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टेस्ट सीरीज में भारत की शानदार जीत की तारीफ करते हुए इसे सबसे बेहतरीन वापसी के साथ मिली जीत में से एक करार दिया। एडीलेड में अपने न्यूनतम टेस्ट स्कोर 36 रन पर आउट होने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से जीती। द ऑस्ट्रेलियन ने कहा कि भारत ने गाबा का किला फतह करके चमत्कार कर दिया। इसने कहा, सिताराहीन, संघर्षरत और चोटिल भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी मजबूत टीम का मानमर्दन किया। फॉक्सस्पोर्ट ने कहा, अगर आप सदमे में है तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। भारत ने हाल ही में बार्डर गावसकर ट्रोफी जीत ली है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे शानदार जीत में से एक। वेबसाइट क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने कहा, इंडियन समर। गाबा में जीत का सिलसिला टूटा। भारत ने विषमताओं को धता बताते हुए गाबा पर शानदार जीत दर्ज की।

रोमा को हराकर स्पेजिया इटालियन कप के क्वार्टर फाइनल में

रोम, एजेंसी। स्पेजिया ने अतिरिक्त समय में नौ खिलाड़ियों के साथ खेल रहे रोमा को 4-2 से हराकर इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रोमा के पूर्व विंगर डेनियल वर्डे और रिकार्डो सैपोनारा ने स्पेजिया की तरफ से अतिरिक्त समय में गोल किये। स्पेजिया क्वार्टर फाइनल में नैपोली से भिड़ेगा। अतिरिक्त समय के पहले दो मिनट में ही खेल का परिदृश्य बदल गया था। रोमा के डिफेंडर जियानलुका मनचिनी और गोलकीपर पॉउ लोपेज को अलग अलग घटनाओं के कारण 30 सेकेंड के अंदर बाहर भेज दिया गया था। मनचिनी को दूसरा पीला कार्ड मिला जबकि लोपेज को लाल कार्ड दिखाया गया। स्पेजिया ने इसका पूरा फायदा उठाकर जीत दर्ज की।

चेल्सी को हराकर प्रीमियर लीग में शीर्ष पर पहुंचा लीस्टर सिटी

लीस्टर,एजेंसी। लीस्टर सिटी ने चेल्सी के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज करके इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल टूनार्मेंट की अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। विल्फ्रेड एनडीडी (छठे मिनट) और जेम्स मैडिसन (41वें मिनट) ने पहले हॉफ में गोल किये जिससे लीस्टर सिटी अंकतालिका में मैनचेस्टर यूनाईटेड और मैनचेस्टर सिटी को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहा। लीस्टर सिटी की यह 12वीं जीत है और उसके 19 मैचों में 38 अंक हो गये हैं। मैनचेस्टर यूनाईटेड के 18 मैचों में 37 और मैनचेस्टर सिटी के 17 मैचों में 35 अंक हैं।

रानी के गोल से महिला हॉकी टीम ने अर्जेंटीना की जूनियर टीम से मैच ड्रा खेला

ब्यूनस आयर्स, एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनल्टी कार्नर पर कई मौके गंवाने के बाद कप्तान रानी रामपाल के चौथे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में किये गये गोल की मदद से आखिर में अर्जेंटीना की जूनियर टीम के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रा खेला। भारतीय टीम यह लगातार दूसरा ड्रा मैच है। उसने दौरे का पहला मैच 2-2 से ड्रा खेला था। भारत ने आक्रामक शुरूआत की और पहले मिनट में ही पेनल्टी कार्नर हासिल किया लेकिन गुरजीत कौर के ताकतवर शॉट को अर्जेंटीनी गोलकीपर ने रोक दिया। इसके बाद पांचवें मिनट में दीप ग्रेस एक्का का

पेनल्टी कार्नर पर लिया गया शॉट बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद अर्जेंटीनी टीम को तीन पेनल्टी कार्नर मिले जिसमें से वह अंतिम वाले को गोल में बदलने में सफल रही। इस तरह से अर्जेंटीना ने 13वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली थी। भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में भी गोल करने के कई मौके बनाये लेकिन वह अर्जेंटीनी गोल में सेंध लगाने में नाकाम रहा। भारतीय टीम को 37वें, 43वें, 48वें और 58वें मिनट में पेनल्टी कार्नर भी मिले लेकिन आखिर में उसे 58वें मिनट में बराबरी का गोल करने में सफलता मिली। रानी ने यह गोल नवनीत कौर के पास पर किया। भारत अगला मैच 23 जनवरी को अर्जेंटीना बी टीम से खेलेगा।

हरभजन का चेन्नई के साथ आईपीएल अनुबंध समाप्त

नई दिल्ली, एजेंसी। अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बुधवार को कहा कि उनका इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ अनुबंध समाप्त हो गया है जिसके साथ उन्होंने शानदार दो साल बिताये। इस 40 वर्षीय खिलाड़ी ने अगले महीने की आईपीएल नीलामी और आगामी सत्र के लिये बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों की सूची घोषित किये जाने से पूर्व यह खुलासा किया। हरभजन ने ट्वीट किया, मेरा चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ अनुबंध समाप्त हो गया है। इस टीम के लिये खेलना शानदार अनुभव रहा। कई सुखद यादें जुड़ी और कुछ अच्छे

दोस्त बने जिन्हें मैं आने वाले वर्षों में भी याद रखूंगा। इन दो शानदार वर्षों के लिये चेन्नई सुपरकिंग्स के प्रबंधन, सहयोगी स्टाफ और प्रशंसकों का आभार। हरभजन चेन्नई की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2018 में दो साल के निलंबन के बाद वापसी करने पर खिताब जीता था।

थाइलैंड ओपन : प्रणीत कोविड-19 पॉजिटिव

रूम में साथ रहने वाले श्रीकांत भी टूर्नामेंट से बाहर

बैंकॉक,एजेंसी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के कारण थाइलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट से हटना पड़ा। दुनिया के पूर्व नंबर-1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को भी प्रणीत के साथ एक ही कमरे में रहने के कारण वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, टूर्नामेंट से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैडमिंटन की इस वैश्विक संस्था ने मंगलवार रात जारी बयान में कहा, ह्यविश्व बैडमिंटन महासंघ पुष्टि करता है कि भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया है और इसलिए वह थाइलैंड ओपन से हट गए हैं। खिलाड़ी का सोमवार को पीसीआर परीक्षण किया गया था जिसमें उनका परिणाम पॉजीटिव आया है। खिलाड़ी को आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उन्हें कम से कम 10 दिन तक अस्पताल में रहना होगा।

ऐसा एतिहासिक दिन रोज-रोज नहीं आता : शास्त्री

ब्रिस्बेन, एजेंसी। भारतीय टीम के प्रमुख कोच रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में मिली शानदार जीत के बाद ड्रेसिंग रुम में टीम के सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ऐसा ऐतिहासिक दिन रोज-रोज नहीं आता है। भारत ने मंगलवार को ब्रिस्बेन के गाबा में चौथे और अंतिम टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन 328 रन के मुश्किल लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए तीन विकेट से जीत हासिल की। भारत ने चार मैचों की सीरीज को 2-1 से जीता और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। भारतीय कोच शास्त्री ने गाबा टेस्ट की ऐतिहासिक जीत के बाद टीम को ड्रेसिंग रुम में सभी खिलाड़ियों और स्टाफ की सराहना करते हुए प्रेरक संदेश दिया और सभी का उत्साह बढाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इन लम्हों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें शास्त्री सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर सराहना कर रहे हैं। शास्त्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, एडिलेड में 36 रन पर आउट होने के बाद आप सभी ने जिस तरह मेलबोर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में वापसी की, वह आपके जजबे, साहस और प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

आस्ट्रेलिया को थोड़ा सख्त रवैया दिखाना चाहिए था : माइकल क्लार्क

मेलबर्न,एजेंसी। पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का मानना है कि आस्ट्रेलिया को ब्रिसबेन में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत की दृढ़ता से निबटने के लिये पहली से लेकर आखिरी गेंद तक थोड़ा सख्त रवैया दिखाना चाहिए था। क्लार्क हालांकि इस घरेलू श्रृंखला में आस्ट्रेलिया की हार का दोष कप्तान टिम पेन को नहीं देते। कई खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान रहे भारत ने मंगलवार को चौथा और अंतिम टेस्ट तीन विकेट से जीतकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की और बोर्डर-गावस्कर ट्राफी बरकरार रखी। पेन की अगुवाई में आस्ट्रेलिया ने 23 टेस्ट मैच खेले जिनमें से उसे केवल 11 में ही जीत मिली। भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में दो हार से उनका रिकार्ड और खराब हो गया है। पेन को 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के मामले के बाद स्टीव स्मिथ की जगह कप्तान बनाया गया था। उनकी न सिर्फ अपनी कप्तानी बल्कि खराब विकेटकीपिंग के कारण भी

आलोचना हो रही है। लेकिन क्लार्क का मानना है कि नकारात्मक मानसिकता के कारण आस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा।

क्लार्क ने बिग स्पोर्ट्स ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि हमारा रवैया कुछ अवसरों पर नकारात्मक रहा क्योंकि हमारे अंदर पराजय का भय था। इसके बजाय हमें सख्त रवैया अपनाकर मैच जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, आखिर में मैच में 20 ओवर रहते हुए हारना या अंतिम गेंद पर हारना मायने नहीं रखता। हमें ट्राफी हासिल करने के लिये यह मैच जीतना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमें मैच की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक इस तरह का रवैया दिखाना चाहिए था। क्लार्क ने कहा कि एक समय था जबकि कप्तान के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब मैं अपने पिता को देखकर बड़ा हुआ तो मैं जिन टीमों में खेलता था उनमें कप्तान जवाबदेह होता था लेकिन समय के साथ यह बदल गया। क्लार्क ने कहा, अब चयनसमिति का अध्यक्ष है, हाई परफोरमेन्स मैनेजर है, मुख्य कोच है जिनके पास अधिक जिम्मेदारियां हैं।